वर्ष 12 • अंक 303 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 7 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

इस साल फिर महंगी दाल बिगाड़ेगी घर का बजट

नरेंद्र मोदी पृष्ठ 14

मोदी ने सीएए पर विपक्ष को घेरा

डॉलर रु. 71.20 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 78.30 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40336 ▲ 287 रुपये | सेंसेक्स 41306.00 ▲ 163.40 | निफ्टी 12138.00 ▲ 48.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12136.30 ▼ 01.60 | ब्रेंट क्रूड 54.70 डॉलर ▼ 0.30 डॉलर

एक नज़र

वोडाफोन आइडिया पोस्टपेड से हटेगा ब्रांड 'आइडिया'

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया अपनी पोस्टपेड सेवाओं से 'आइडिया' नाम हटा देगी। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। कंपनी अपने प्रीपेड ग्राहकों को वोडाफोन एवं आइडिया ब्रांड से सेवाएं देना जारी रखेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वोडाफोन रेड पोस्टपेड प्लान ग्राहकों को वोडाफोन एवं आइडिया ब्रांड के सभी स्टोरों एवं डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध रहेगा।

तत्काल ऑनलाइन पैन की सुविधा इसी महीने से

सरकार 'आधार' की जानकारियां प्रदान करने पर तत्काल ऑनलाइन पैन जारी करने की सुविधा इस महीने से शुरू करने जा रही है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 1 फरवरी को पेश आम बजट 2020-21 में स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन करने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव दिया था। बजट में कहा गया था कि इसके लिए आधार के जरिए तत्काल आधार पर पैन जारी करने की सुविधा दी जाएगी।

हीरो मोटोकॉर्प का कर पूर्व मुनाफा 9.14 प्रतिशत घटा

चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प का कर पूर्व मुनाफा 9.14 प्रतिशत कम रहा है। आलोच्य अवधि में यह आंकड़ा 1,044.44 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,149.63 करोड़ रुपये रहा था। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य वित्तीय अधिकारी निरंजन गुप्ता ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के बीच दोपहिया वाहन उद्योग के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। कंपनी की कुल आय आलोच्य अवधि में 10.7 प्रतिशत कम होकर 7,259.39 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 8,128.16 करोड़ रुपये थी। पृष्ठ 2

एआईएफ प्रदर्शन के मानकीकरण पर दिशानिर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) के प्रदर्शन के मानकीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बाजार नियामक के इस कदम का मकसद खुलासा मानकों में तेजी लाना और निवेशकों की योजना के प्रदर्शन के आकलन में मदद करना है। नियामक ने करीब दो महीने पहले इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया था। सेबी ने गुरुवार को कहा कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रदर्शन में पारदर्शिता लाने के लिए लचीले रुख की जरूरत है। नियामक ने कहा कि प्रदर्शन के मानकीकरण से निवेशकों को एआईएफ उद्योग के प्रदर्शन की समीक्षा में मदद मिलेगी।

चीन ने की अमेरिकी आयात पर शुल्क कटौती की घोषणा

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मसले पर प्राथमिक समझौता होने के एक महीने बाद चीन ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले 75 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क की दर 14 फरवरी से आधा करने की घोषणा की है। चीन की राज्य शुल्क आयोग परिषद के अनुसार यह कटौती 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत शुल्क के दायरे में रखी गई वस्तुओं पर लागू होगी। यह शुल्क अमेरिका से आयात होने वाली करीब 1,700 वस्तुओं पर सितंबर में लगाया गया था। अमेरिका से आयात होने वाले जिन उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था, उनमें समुद्री खाद्य उत्पाद, मुर्गीपालन से जुड़े उत्पाद और सोयाबीन शामिल थे।

त्यापार गोष्ठी

आम बजट पर आपकी राय ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या आरबीआई के कदम से बैंकिंग तंत्र में बढ़ेगी नकदी

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या मारुति के पीछे हटने से ई-वाहन में अन्य कंपनियों को मिलेगा मौका? हां **62.50%** नहीं **37.50%**

रीपो यथावत मगर घटेगी ब्याज दर

रीपो 5.15 फीसदी पर बरकरार, राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए नहीं खरीदेगा बॉन्ड

अरूप रॉय
मुंबई, 6 फरवरी

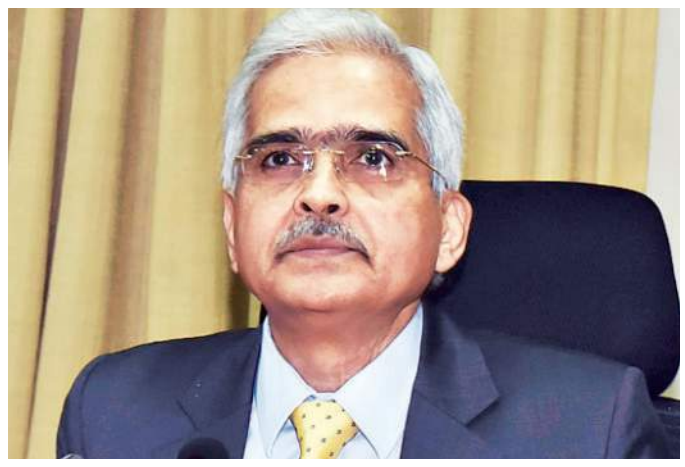

> हमारे पास दरों में कटौती के लिए नीतिगत गुंजाइश है लेकिन यह आगे आने वाली स्थिति पर निर्भर करेगा। एमपीसी 2019 में सक्रिय थी और 2020 में और ज्यादा सक्रिय रहेगी।
>
> शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति में आज नीतिगत दरों और रुख को यथावत रखा लेकिन बैंकों के लिए फंड की लागत कम करने के लिए गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया। इससे बैंक अपनी उधारी दरों में और कटौती कर सकेंगे और साथ ही उन्हें खपत मांग को पटरी पर लाने के लिए खुदरा उधारी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से दरों को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया क्योंकि मुद्रास्फीति परिदृश्य 'बेहद अनिश्चित' बना हुआ है।

केंद्रीय बैंक ने रीपो दर 5.15 फीसदी पर यथावत रखी और उदार नीतिगत रुख में भी कोई बदलाव नहीं किया। बैंक ने साथ ही साफ किया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर दरों में कटौती की जाएगी। अभी मुद्रास्फीति की दर 7.4 फीसदी है और ऐसी स्थिति में दरों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मौद्रिक नीति में और कदम उठाए जाने की गुंजाइश है लेकिन यह आगे आने वाली परिस्थिति पर निर्भर करेगा। एमपीसी 2019 में सक्रिय रही थी और 2020 में वह इससे भी ज्यादा सक्रिय रहेगी।'

दास ने कहा कि भले ही इस बार का निर्णय अनुमानों के अनुरूप है, लेकिन रिजर्व बैंक की भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए। रिजर्व बैंक के पास आर्थिक वृद्धि दर में जारी नरमी से निपटने के लिए और भी कई अन्य उपाय हैं।

आरबीआई ने कुछ नए उपायों की घोषणा की है जिनकी विश्लेषकों ने सराहना की है। एसपीजेएमआर में एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण ने कहा, 'यह नीति बेहद उदार है। दरों में कटौती के बिना आरबीआई ने इससे भी ज्यादा हासिल कर लिया है।'

केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि अगर वे वाहन, आवास और एसएमई क्षेत्रों को कर्ज देते हैं तो उनके जमा आधार में से उतनी रकम कम हो सकती है जिससे उन्हें निर्धारित 4 फीसदी नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में राहत मिल सकती है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था में नकदी झोंकने और निकालने के तरीकों में भी बदलाव किया है। हालांकि उसने साथ ही साफ किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह परंपरागत तरीके अपनाने से नहीं हिचकेगा। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय बैंक ने दीर्घकालिक रीपो परिचालन शुरू किया है। ये दो तरह की नकदी प्रतिभूतियां होंगी जिन्हें बैंक मौजूदा रीपो दर पर एक साल और तीन साल की अवधि के लिए पैसा उधार लेने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल एक लाख करोड़ रुपये तक उधार लेने में ही किया जा सकता है।

दास ने कहा कि यह बेहतर मौद्रिक नीति हस्तांतरण का प्रयास है क्योंकि हम इसे नीतिगत दर पर दे रहे हैं। इस तरह हम बैंकिंग व्यवस्था में एक लाख करोड़ रुपये झोंकना चाहते हैं जिससे बैंकों को अपनी उधारी दरें घटाने में मदद मिलेगी। दास ने कहा कि आरबीआई राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए सीधे तौर पर सरकार से बॉन्ड नहीं खरीदेगा। ■ संबंधित खबरें : पृष्ठ 4

इमामी सीमेंट को खरीदेगा निरमा समूह

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 6 फरवरी

सौदे का करार

- **5,500** करोड़ रुपये में होगा सौदा
- इमामी सीमेंट की उत्पादन क्षमता : कुल **83** लाख टन सालाना
- कहां-कहां संयंत्र जाजपुर (ओडिशा) : **20** लाख टन
- पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) : **25** लाख टन रिसड़ा (छत्तीसगढ़) : **30** लाख टन
- भभुआ (बिहार) : **8** लाख टन

इमामी समूह ने आज घोषणा की कि उसने नूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निरमा समूह की इकाई) के साथ इमामी सीमेंट में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए बाध्यकारी करार किया है। यह सौदे का मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपये होगा।

इमामी सीमेंट पर 2,000 से 2,200 करोड़ रुपये का कर्ज है और 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज शेयर के एवज में लिया गया है। इस सौदे से इमामी को करीब 2,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह कदम इमामी द्वारा समूह स्तर पर कर्ज को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। श्री सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट सहित कई निजी इक्विटी निवेशकों ने इमामी सीमेंट के अधिग्रहण में दिलचस्पी दिखाई थी। कंपनी का एक एकीकृत सीमेंट संयंत्र और तीन ग्राइंडिंग इकाइयां हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता करीब 83 लाख टन सालाना है। इमामी समूह के निदेशक मनीष गोयनका ने कहा कि यह सौदा अपने समूह को कर्ज-मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, 'मुझे गर्व है कि इमामी सीमेंट ने काफी कम समय में उपलब्धियां हासिल की हैं और हमारा मानना है कि नूवोको के तौर पर हमने सही खरीदार तलाशा है जो सभी शेयरधारकों के हित में आगे कारोबार का और विस्तार करने में सक्षम होगी।'

इमामी समूह के निदेशक आदित्य अग्रवाल ने कहा कि इस सौदे से प्रवर्तकों की गिरवी हिस्सेदारी कम होगी। इमामी सीमेंट के कर्ज को समायोजित करने के बाद प्रवर्तक स्तर पर कर्ज करीब 600 करोड़ रुपये का होगा। समूह कर्ज को कम करने के विभिन्न विकल्पों को अपना रहा है। पिछले साल इमामी समूह के प्रवर्तकों ने कर्ज कम करने के लिए इमामी में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी करबी 1,230 करोड़ रुपये में बेची थी। उस समय कर्ज 3,300 करोड़ रुपये था जो कम होकर 2,200 करोड़ रुपये रह गया है।

अग्रवाल ने कहा कि इमामी सीमेंट ने इक्विटी बाजार में खुद को मजबूत ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है और उच्चतम मानक वाले परिचालन एवं उच्च गुणवत्ता के उत्पादों ने बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद की। राजस्थान में निरमैक्स के कारोबार का अधिग्रहण और विलय पूरा करने के साथ ही नूवोको पूर्वी भारत की अग्रणी सीमेंट कंपनियों में से एक बन गई है। इस सौदे से उसकी कुल उत्पादन क्षमता 2.35 करोड़ टन हो जाएगी। नूवोको के चेयरमैन हिरेन पटेल ने कहा, 'यह अधिग्रहण नूवोको के प्रमुख बिल्डिंग मैटीरियल कंपनी बनने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।' सौदा भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की मंजूरी पर निर्भर करेगा और इसके 3 से 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

लक्ष्मी विलास की दौड़ में डीबीएस, कापरी ग्लोबल

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 6 फरवरी

निवेश की बात

- लक्ष्मी विलास बैंक ने आरबीआई को सौंपी संभावित निवेशकों की सूची
- वित्त वर्ष के अंत तक निवेशक के नाम का हो सकता है ऐलान
- लक्ष्मी विलास बैंक को पूंजी की है सख्त जरूरत
- इंडियाबुल्स हाउसिंग के साथ विलय का प्रस्ताव हो गया था खारिज

पूंजी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक को जल्द ही पैसा लगाने वाला निवेशक मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बुधवार को संभावित निवेशकों की एक सूची सौंपी है जिसमें सिंगापुर के डीबीएस बैंक और कापरी ग्लोबल के नाम भी शामिल हैं।

30 जून, 2019 को लक्ष्मी विलास बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 6.46 फीसदी और सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 17.3 फीसदी थी। इसके देखते हुए आरबीआई ने सितंबर 2019 को इसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई में डाल दिया था। आरबीआई ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के साथ इसके विलय के प्रस्ताव को पिछले महीने खारिज कर दिया था, जिसके बाद से बैंक काफी कम पूंजी के साथ परिचालन कर रहा है। बैंक संभावित निवेशकों के साथ भी लगातार बात कर रहा है। घटनाक्रम के जानकार सूत्र ने बताया कि बैंक 2019 की शुरुआत से ही कापरी ग्लोबल और डीबीएस बैंक इंडिया के साथ बात कर रही थी।

इस बीच लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति और बिगड़ रही है। सितंबर 2019 तिमाही में उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात घटकर 5.56 फीसदी रह गया जबकि सकल एनपीए 21.25 फीसदी पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2018 से ही बैंक को घाटा हो रहा है और इसका बाजार पूंजीकरण 5 अप्रैल, 2019 (जब इंडियाबुल्स हाउसिंग के साथ सौदे की घोषणा हुई थी) से 83 फीसदी घटकर 482 करोड़ रुपये रह गया है।

एक अन्य सूत्र ने कहा कि निवेशक के नाम की घोषणा वित्त वर्ष 2020 के अंत तक की जा सकती है और बैंक को तत्काल पूंजी मिल सकती है। मामले के जानकार एक शख्स ने कहा, 'बैंक को अपने बहीखाते को दुरुस्त करने के लिए पूंजी की सख्त जरूरत है।'

ऐसा समझा जाता है कि डीबीएस बैंक और कापरी ग्लोबल इस बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में है। वर्ष 2016 में आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व के नियमों में ढील दी थी जिसके तहत विदेशी बैंक भारत के निजी बैंक में 10 फीसदी तक हिस्सा खरीद सकते हैं।

एक अन्य शख्स ने कहा कि सीबीएस बैंक की तरह डीबीएस बैंक इंडिया के लिए भी कुछ रियायत दी जा सकती है। प्रेम वत्स प्रवर्तित फेयरफैक्स ने 2018 में सीबीएस बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।

डीबीएस बैंक इंडिया देश में भारतीय सहायक इकाई शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक है। वित्त वर्ष 2019 में इसे 14.5 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2019 में बैंक की उधारी 18,108 करोड़ रुपये और जमाएं 33,828 करोड़ रुपये रही।

कापरी ग्लोबल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसके प्रवर्तक राजेश शर्मा है। लक्ष्मी विलास बैंक में इसकी 4.62 फीसदी हिस्सेदारी है।

एफएमसीजी उत्पादों के बढ़ेंगे दाम

धीमी गति से आगे बढ़ रहे उपभोक्ता सामान के बाजार को आगामी कुछ महीने में कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा क्योंकि कच्चे माल की लागत लगातार बढ़ रही है। देश की दो अग्रणी साबुन निर्माता गोदरेज कंज्यूमर (जीसीपीएल) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के अधिकारियों ने कहा कि सबसे पहले साबुन के दाम बढ़ेंगे। जीसीपीएल ने कहा कि कंपनी ने हाल में साबुन के दाम 5 फीसदी बढ़ाए हैं और आगामी महीनों में इसमें और इजाफे पर विचार करेगी। पिछले हफ्ते एचयूएल ने मार्च में साबुन की कीमतों में 5-6 फीसदी की बढ़ोतरी करने की बात कही थी। पृष्ठ 2

वधावन की संपत्तियां जब्त करेगा ईडी!

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस के प्रवर्तक कपिल वधावन की भारत और विदेश में कम से कम 20 संपत्तियों की पहचान की है जिनकी कीमत करीब 3,000 करोड़ रुपये है। ईडी कुछ हफ्तों में इन संपत्तियों की संभावित जब्ती के लिए इनका आकलन कर रहा है। वधावन की इन संपत्तियों में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1,000 करोड़ रुपये की 12,000 वर्गफुट जमीन, थाइलैंड में 50 करोड़ रुपये का विला और ब्रिटेन तथा अमेरिका में फ्लैट और ऑफिस शामिल हैं। उनकी ये संपत्तियां भारतीय संपत्तियों से अलग हैं। पूछताछ के दौरान ईडी ने पाया कि डीएचएफएल ने कुछ मुखौटा फर्मों की मदद से अपने शेयर कीमतों में कई मौकों पर गड़बड़ी की। पृष्ठ 2

अब अदाणी ग्रीन में टोटाल का निवेश

अदाणी समूह फ्रांस की प्रमुख तेल कंपनी टोटाल के साथ एक और साझेदारी करने जा रहा है। इस बार समूह अपने सौर ऊर्जा कारोबार के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने की तैयारी में है। अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्वामित्व वाली 2,148 मेगावॉट सौर क्षमता में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टोटाल 51 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। अदाणी ग्रीन ने कहा है कि उसने एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 50 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए टोटाल गैस ऐंड पावर बिजनेस सर्विसेज एसएएस के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पृष्ठ 2

कोरोना के डर से सहमा पोल्ट्री कारोबार

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 6 फरवरी

- पोल्ट्री उत्पादों के दाम **10** प्रतिशत तक घटे
- मुर्गे एवं अंडे की मांग में **10-15** प्रतिशत तक की कमी
- मार्च अंत तक इनकी मांग सुधरने की उम्मीद
- छोटे पोल्ट्री कारोबारियों ने बंद किए कारोबार

देश भर में पोल्ट्री उत्पादों (मुर्गा, अंडा) की कीमतों में पिछले दो दिनों में 10 प्रतिशत गिरावट आई है। दरअसल सोशल मीडिया समूहों में यह अफवाह फैली है कि पक्षियों में कोरोनावायरस का संक्रमण हो गया है। कीमतों में अचानक गिरावट के बाद पुणे में पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर चिकन की कीमत 65 रुपये और दिल्ली में 72 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। पिछले सप्ताह तक इनकी कीमतें क्रमश: 73 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम थीं। इसी तरह, अंडे की कीमतें कम होकर 3.75 रुपये (प्रति अंडा) रह गई हैं।

चीन में कोरोनावायरस के संक्रमण के बाद भारत में भी इसके कुछ मामले दिखे हैं। इनके बीच ऐसी अफवाह जोर पकड़ रही है कि पक्षियों के जरिये इस खतरनाक वायरस का प्रसार हो रहा है। आम तौर पर स्तनधारी प्राणी इस वायरस के स्रोत होते हैं जिनसे मनुष्यों में संक्रमण फैलता है। समझा जा रहा है कि चीन में चमगादड़ से कोरोनावायरस का प्रसार हुआ है। पोल्ट्री उत्पादों की कीमतों में कमी पर गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम यादव ने कहा, 'पिछले दो दिनों में अचानक पोल्ट्री उत्पादों उत्पादों की कीमतें 10-15 प्रतिशत तक घट गई हैं। ऐसी अफवाह फैली है कि जानवर और मुर्गियों से यह वायरस फैल रहा है।' यादव ने कहा कि कोरोनावायरस एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5एन1) से अलग है, इसलिए पक्षियों में इसके संक्रमण की गुंजाइश नहीं है।

इस बीच, मुर्गीपालक कीमतें अचानक कम होने से परेशान हैं, क्योंकि इससे उनके मुनाफे पर सीधी चोट पड़ी है। मानक ब्रॉयलर चिकन का कारोबार पिछले एक साल से भी अधिक समय से 80 रुपये की उत्पादन लागत से नीचे हो रहा है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे बड़े मुर्गी उत्पादक राज्यों में किसान ने समय-समय पर इन उत्पादों की कीमतों में कमी के खिलाफ प्रतिरोध किया है। वे सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सस्ती दरों पर मुर्गियों के लिए चारे की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं।

छोटे पोल्ट्री कारोबारियों ने तो अपना कारोबार तक बंद कर दिया है। बड़े स्तर पर मुर्गीपालन कारोबार में जुटी इकाइयां भी नुकसान में आ गई हैं। वेंकटेश्वर हैचरीज के महाप्रबंधक के जी आनंद ने कहा, 'कारोबार के लिहाज से कमजोर समय होने के कारण पोल्ट्री उत्पादों की मांग कम है। कोरोनावायरस की अफवाह से इनकी मांग और कम हो गई है।'

चीन गए विदेशियों के भारत आने पर रोक

आव्रजन ब्यूरो ने एक नोटिस में कहा है कि वैसे विदेशी नागरिक जो 15 जनवरी को या उसके बाद चीन गए हैं, उनका भारत में प्रवेश वर्जित होगा। चीन में कोरोनावायरस के मामले में तेजी आने के बाद यह कदम उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका और कई अन्य देशों ने विदेशी नागरिकों पर ऐसे ही समान प्रतिबंध लगाए हैं। पृष्ठ 14

20 फीसदी तक घटेगा चावल का निर्यात!

अमेरिका-ईरान के गतिरोध और कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से इस साल भारत के चावल निर्यात में 18 से 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। पिछले साल से ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान को किया जाने वाले बासमती चावल निर्यात के संबंध में अनिश्चितता बनी रही है। पृष्ठ 6

खबरों में रहे स्टॉक

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस

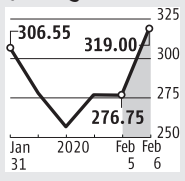

वाहन, आवास एवं एमएसएमई क्षेत्र में उधारी को प्रोत्साहन

₹ 276.75 पिछला बंद भाव
₹ 319.00 आज का बंद भाव
▲ 15.27 %

अजंता फार्मा

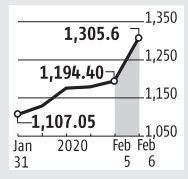

तीसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 88 फीसदी बढ़ा

₹ 1,194.40 पिछला बंद भाव
₹ 1,305.60 आज का बंद भाव
▲ 9.31 %

भारती एयरटेल

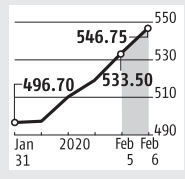

बाजार पूंजीकरण 3 लाख करोड़ रुपये के पार

₹ 533.50 पिछला बंद भाव
₹ 546.75 आज का बंद भाव
▲ 2.48 %

एवेन्यू सुपरमार्ट्स

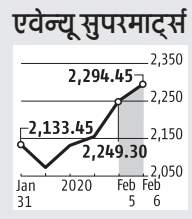

करीब 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए क्यूआईपी जारी किया

₹ 2,249.30 पिछला बंद भाव
₹ 2,294.45 आज का बंद भाव
▲ 2.01 %

ग्रैन्यूल्स इंडिया

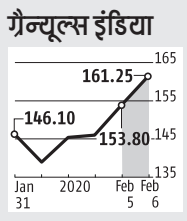

सहायक इकाई को दवा के लिए यूएसएफडी से मंजूरी

₹ 153.80 पिछला बंद भाव
₹ 161.25 आज का बंद भाव
▲ 4.84 %

संक्षेप में

यूको बैंक का नुकसान 960 करोड़ रुपये

यूको बैंक का कर पूर्व नुकसान दिसंबर तिमाही में 960 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,018 करोड़ रुपये रहा था। कुल उधारी के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए 19.45 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 27.39 फीसदी रहा था। शुद्ध एनपीए 6.34 फीसदी रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 12.48 फीसदी रहा था। *बीएस*

यूनाइटेड बैंक का शुद्ध लाभ 129 करोड़ रुपये

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 129 करोड़ रुपये रहा जबकि बैंक ने पिछले साल की समान अवधि में 1,585 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान दर्ज किया था। कुल उधारी के प्रतिशत के तौर पर सकल एनपीए 15.48 फीसदी रहा। *बीएस*

एनएमडीसी का शुद्ध लाभ 13 फीसदी घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी का दिसंबर, 2019 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 12.75 फीसदी घटकर 1,375 करोड़ रुपये रह गया। *भाषा*

अदाणी की टोटाल संग दूसरी साझेदारी

अदाणी ग्रीन संग संयुक्त उद्यम में 51 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी टोटाल

अमृता पिल्लई
मुंबई, 6 फरवरी

अदाणी समूह फ्रांस की प्रमुख तेल कंपनी टोटाल के साथ दूसरी साझेदारी करने जा रहा है। इस बार समूह अपने सौर ऊर्जा कारोबार के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने की तैयारी में है। अदाणी ग्रीन एनर्जी के स्वामित्व वाली 2,148 मेगावॉट सौर क्षमता में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टोटाल 51 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी।

अदाणी ग्रीन ने आज जारी एक बयान में कहा है कि उसने एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 50 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए करीब 51 करोड़ डॉलर का निवेश करने के लिए टोटाल गैस ऐंड पावर बिजनेस सर्विसेज एसएएस के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

बयान में कहा गया है कि संयुक्त उद्यम कंपनी के पास 2,148 मेगावॉट क्षमता की चालू सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी जिनकी 100 फीसदी हिस्सेदारी फिलहाल अदाणी ग्रीन के पास है। संयुक्त उद्यम में शेष 50 फीसदी हिस्सेदारी अदाणी ग्रीन के पास रहेगी। सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार देश के 11 राज्यों में विस्तृत होगा।

चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इस सौदे के पूरे होने की उम्मीद है। अदाणी ग्रीन इस सौदे से प्राप्त रकम का इस्तेमाल नई परियोजनाओं के इक्विटी वित्त पोषण में करेगी। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'टोटाल के साथ हमारी दीर्घावधि साझेदारी का विस्तार एजीईएल में हमारे अक्षय ऊर्जा कारोबार तक करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस निवेश से भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा होंगी और अदाणी समूह सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।'

फिलहाल 2,148 मेगावॉट का पोर्टफोलियो सौर ऊर्जा में अदाणी ग्रीन का कुल परिचालन पोर्टफोलियो है। जबकि कंपनी 475 मेगावॉट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता तैयार कर रही है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अदाणी ग्रीन का परिचालन पोर्टफोलियो 347 मेगावॉट है। कंपनी की नजर 2025 तक 15 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि फिलहाल निर्माणाधीन पोर्टफोलियो को टोटाल के साथ नवगठित संयुक्त उद्यम को हस्तांतरित करने की कोई योजना नहीं है।

गुजरात के इस कारोबारी समूह की टोटाल के साथ यह दूसरी साझेदारी है। पिछले साल अक्टूबर में टोटाल ने करीब 5,700 करोड़ रुपये में गौतम अदाणी के नेतृत्व वाली अदाणी गैस में करीब 37.4 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक निश्चित समझौता किया था। इस सौदे को दो भागों- आम शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश और कंपनी के प्रवर्तकों से हिस्सेदारी की खरीद- में निष्पादित किया गया। अदाणी गैस ने उम्मीद जताई है कि यह सौदा इसी साल मार्च तक पूरा हो जाएगा।

जहां तक टोटाल का सवाल है तो यह सौदा 2025 तक उसके 25 गीगावॉट क्षमता के अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो तैयार करने के लक्ष्य की दिशा में उठाया गया कदम है।

टोटाल के मुख्य कार्याधिकारी पैट्रिक पुयाने ने कहा, 'करीब 2 गीगावॉट की सौर परियोजनाओं में यह निवेश भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी की व्यापकता में वास्तविक बदलाव को दर्शाता है। आगामी वर्षों में भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि की उल्लेखनीय क्षमता मौजूद है। इससे हमें 2015 तक 25 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।'

सौर ऊर्जा में अदाणी संग टोटाल

- टोटाल 2,148 मेगावॉट सौर क्षमता में आंशिक हिस्सेदारी लेगी
- अदाणी टोटाल संयुक्त उद्यम के तहत सौर परियोजनाएं आएंगी
- संयुक्त उद्यम में 50 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टोटाल 51 करोड़ रुपये का निवेश करेगी
- संयुक्त उद्यम में शेष हिस्सेदारी अदाणी ग्रीन के पास रहेगी
- इसी साल मार्च के अंत तक सौदा पूरा होने की उम्मीद

कमजोर एफएमसीजी बाजार में बढ़ रहे दाम

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 6 फरवरी

धीमी गति से आगे बढ़ रहे उपभोक्ता सामान के बाजार को आगामी कुछ महीने में कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा क्योंकि इनपुट लागत लगातार बढ़ रही है। देश की दो अग्रणी साबुन निर्माता गोदरेज कंज्यूमर (जीसीपीएल) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के अधिकारियों ने कहा कि सबसे पहले साबुन के दाम बढ़ेंगे।

गुरुवार को जीसीपीएल के मुख्य कार्याधिकारी (भारत व सार्क क्षेत्र) सुनील कटारिया ने क हा, कंपनी ने हाल में साबुन के दाम 5 फीसदी बढ़ाए हैं और आगामी महीनों में इसमें और इजाफे पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा, साबुन पर महंगाई का दबाव काफी ज्यादा है। हाल में पहले दौर की कीमत बढ़ोतरी हुई है। इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हम नपा-तुला कदम उठाएंगे।

पिछले हफ्ते एचयूएल के मुख्य वित्त अधिकारी श्रीनिवास पाठक ने कहा था कि इनपुट लागत के दबाव को कम करने के लिए मार्च में साबुन की कीमतों में 5-6 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।

पाठक ने कहा, पिछले छह महीने में देसी पाम तेल की कीमतें 46 फीसदी बढ़ी हैं। साबुन बनाने में पाम तेल मुख्य कच्चा माल है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें 20 फीसदी घटी हैं, लेकिन यह अभी भी बहुत राहत नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, जिंस व मुद्रा में उतारचढ़ाव बना हुआ है। जब बाजार की बढ़त की रफ्तार सुस्त है तो इन चीजों पर नजर रखने की दरकार है।

कच्चा तेल, दूध व दलहन की कीमतों में उतारचढ़ाव के बीच गुरुवार को केंद्रीय बैंक ने जनवरी-मार्च 2020 में खुदरा महंगाई 6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया। आरबीआई ने कहा कि आगामी महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी का कुल परिदृश्य काफी अनिश्चित बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को उत्पादों के महंगे दाम से दो-चार होना पड़ेगा।

एफएमसीजी बाजार पहले ही सुस्त बढ़ोतरी का सामना कर रहा है और दिसंबर 2019 की तिमाही में एफएमसीजी की रफ्तार छह तिमाही में सबसे कम यानी 6.6 फीसदी रही। जुलाई-सितंबर 2018 में एफएमसीजी बाजार की रफ्तार सबसे ज्यादा 16.2 फीसदी रही थी, जो बताता है कि धारणा अभी भी कमजोर बनी हुई है। यह कहना है बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का।

नीलसन और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने हाल में संकेत दिया था कि आगामी दिनों मे एफएमसीजी बाजार की बढ़त की रफ्तार में बदलाव होगा, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का संशय बना हुआ है। कटारिया ने कहा, ढांचागत मांग का मसला बना हुआ है और थोड़ी नरमी के साथ सुधार नजर आएगी। इस मामले में पहले शहरी इलाकों में सुधार दिखेगा, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में।

नीलसन ने कहा था कि ग्रामीण भारत में बढ़त की रफ्तार दिसंबर तिमाही में घटकर 5.2 फीसदी रह गई, जो एक साल पहले 18 फीसदी के उच्चस्तर पर थी। शहरी इलाकों की रफ्तार भी घटी है और दिसंबर तिमाही में यह 7.4 फीसदी रही जबकि एक साल पहले 14 फीसदी रही थी।

ग्रामीण बनाम शहरी वृद्धि (% में)

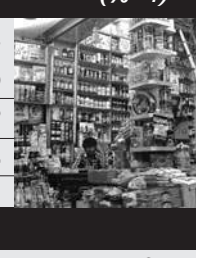

क्षेत्र	अक्टूबर- 18 दिसंबर	अक्टूबर- दिसंबर 19
ग्रामीण	18	5.2
शहरी	14	7.4

स्रोत : नीलसन

बढ़ते दामों का रुख

जिंस	अगस्त 19	फरवरी 19	वृद्धि
*पाम तेल	526	768	46 %
**पाम फैटी एसिड	375	667	78 %

*रुपये प्रति 10 किलो, **डॉलर प्रति टन

एस्सार के लिए आर्सेलर का 1.6 अरब डॉलर का योगदान

एस्सार स्टील इंडिया (अब एएम/एनएस इंडिया) के अधिग्रहण के लिए आर्सेलरमित्तल का इक्विटी योगदान 1.6 अरब डॉलर है। कंपनी ने 2019 के वित्तीय नतीजे जारी करते हुए यह घोषणा की।

आर्सेलरमित्तल ने इसे 2019 की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि एस्सार का अधिग्रहण उसके लिए पांचवां इस्पात स्तंभ है।

एस्सार के अधिग्रहण के लिए अपने इक्विटी योगदान के बावजूद वर्ष 2019 के दौरान विलय एवं अधिग्रहण पर कंपनी के खर्च की भरपाई पोर्टफोलियो को युक्तिसंगत बनाकर किया गया। इसमें जहाजरानी क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम का गठन भी शामिल है। *बीएस*

निफ्टी में डाबर को जगह!

समी मोडक
मुंबई, 6 फरवरी

डाबर इंडिया को निफ्टी-50 इंडेक्स में येस बैंक की जगह शामिल किया जा सकता है। इंडेक्स में शामिल करने के मानकों का अध्ययन करने वाले विश्लेषकों का ऐसा मानना है। अगर ऐसा होता है तो आयुर्वेद पर ध्यान केंद्रित करने वाली फर्म इस इंडेक्स में शामिल होने वाली तीसरी एफएमसीजी कंपनी होगी। डाबर, गोदरेज कंज्यूम प्रॉडक्ट्स (जीसीपीएल) और श्री सीमेंट निफ्टी में शामिल किए जाने को लेकर अग्रिम पंक्ति में हैं।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद कार्की ने कहा, छह माह के औसत फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण के आधार पर डाबर, जीसीपीएल और श्री सीमेंट में मामूली अंतर है। हालांकि निफ्टी इंडेक्स में 27 मार्च में होने वाले आगामी बदलाव में येस बैंक की जगह डाबर ले सकती है। अगस्त में हुए पिछले बदलाव के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले इंडिया ने एनबीएफसी कंपनी इंडियाबुल्स हाउसिंग की जगह ली थी। एक साल पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने इंडेक्स में तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) की जगह ली थी।

उपभोक्ता शेयरों को ऐसे समय में शामिल किया जा रहा है जब इस क्षेत्र का मूल्यांकन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सापेक्षिक सुरक्षा व उच्च रिटर्न अनुपात के कारण निवेशकों ने पिछले दो वर्षों में एफएमसीजी शेयरों में काफी निवेश किया है। विश्लेषकों ने कहा कि एफएमसीजी शेयरों को शामिल किए जाने से उतारचढ़ाव घटेगा, लेकिन मूल्यांकन में इजाफा होगा। ज्यादातर एफएमसीजी शेयर उच्च पीई अनुपात पर कारोबा कर रहे हैं।

हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा घटा

बीएस संवादाता/एजेंसियां
चेन्नई/मुंबई, 6 फरवरी

हीरो मोटोकॉर्प का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 9.14 फीसदी की गिरावट के साथ 1,044.44 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,149.63 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के शुरुआती संकेत मिले हैं, जो उद्योग को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में कायापलट की उम्मीद है।

कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी निरंजन गुप्ता ने कहा, अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच दोपहिया उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है। शुरुआती संकेतक मसलन सकारात्मक रबी फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, जो उद्योग की मदद कर सकता है।

गुप्ता ने कहा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आम बजट में की गई घोषणा का परिणाम सामने आने में लंबा समय लगेगा। हालांकि दोपहिया उद्योग के स्थायी सुधार में थोड़ा वक्त लगेगा। हमें लगता है कि नए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सकारात्मक कायापलट देखने को मिलेगा।

कंपनी की कुल आय इस तिमाही में 10.7 फीसदी घटकर 7,259.39 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 8,128.16 करोड़ रुपये रही थी। दिसंबर तिमाही में कंपनी का एबिटा एकल आधार पर 10.39 फीसदी रहा, जो 14.8 फीसदी का मार्जिन प्रतिबिंबित करता है जबकि पिछले साल की समान अवधि में मार्जिन 14 फीसदी रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी ने पहला बीएस-6 मोटरसाइकल स्प्लेंडर आईस्मार्ट और उसके बाद एचएफ-डीलक्स उतारा। कंपनी नए उत्सर्जन मानकों के मुताबिक वाहनों की पूरी श्रृंखला बदलने की तैयारी कर रही है और कंपनी की योजना फरवरी के मध्य तक बीएस-4 वाहनों का उत्पादन बंद करने की है।

कॉग्निजेंट का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर

प्रमुख आईटी सेवा कंपनी कॉग्निजेंट ने दिसंबर 2019 तिमाही में बाजार के अनुमानों को धत्ता बताते हुए उम्मीद से बेहतर राजस्व वृद्धि के आंकड़े दर्ज किए हैं। हालांकि 2020 के लिए राजस्व अनुमान कमजोर रहा क्योंकि उसने चालू वर्ष के दौरान राजस्व में 2 से 4 फीसदी की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

न्यू जर्सी की आईटी कंपनी ने कहा है कि यह आकलन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि सामग्री सेवा करोबार टीनेक से आईटी कंपनी के बाहर होने के निर्णय का प्रभाव 110 आधार अंकों का होगा। राजस्व वृद्धि का यह अनुमान उसकी प्रतिस्पर्धी टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजिज के अनुमानों के मुकाबले कम हो सकता है। हालांकि इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने अनुमान अभी जारी नहीं किए हैं।

चौथी तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 39 फीसदी घटकर 39.5 करोड़ डॉलर रह गया जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 64.8 करोड़ डॉलर रहा था। कंपनी जनवरी से दिसंबर की अवधि को वित्त वर्ष मानती है। शुद्ध लाभ में गिरावट की मुख्य वजह पुनर्गठन शुल्क में बढ़ोतरी रही जो एक साल पहले के 70 लाख डॉलर से बढ़कर 10.1 करोड़ डॉलर हो गया। तिमाही के दौरान राजस्व स्थिर मुद्रा पर 4.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4.3 अरब डॉलर हो गया। जबकि इस दौरान परिचालन मार्जिन 17 फीसदी पर लगभग स्थिर रहा। *बीएस*

सन फार्मा का शुद्ध लाभ 26 फीसदी घटा

दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज का दिसंबर 2019 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 26.43 फीसदी घटकर 913.52 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1,241.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत परिचालन आय 8,038.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,656.71 करोड़ रुपये रही थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने एक रुपये के शेयर पर तीन रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। बीएसई में कंपनी का शेयर 1.13 फीसदी की बढ़त के साथ 430.95 रुपये पर पहुंच गया।

कपिल वधावन की 3,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 6 फरवरी

प्रवर्तन निदेशालय ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) के प्रवर्तक कपिल वधावन की भारत व विदेश में कम से कम 20 संपत्तियों की पहचान की है, जो करीब 3,000 करोड़ रुपये की है। प्रवर्तन निदेशालय कुछ हफ्तों में इन संपत्तियों की संभावित जब्ती के लिए इसका आकलन कर रहा है। वधावन की इन संपत्तियों में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में 1,000 करोड़ रुपये की 12,000 वर्गफुट की जमीन, थाइलैंड में 50 करोड़ रुपये का विला और ब्रिटेन व अमेरिका में फ्लैट व ऑफिस शामिल है।

ये संपत्तियां भारतीय संपत्तियों से अलग हैं। भारत की संपत्ति में मुंबई के खार में चार फ्लैट (125 करोड़ रुपये) और उसी इलाके में 30 करोड़ रुपये का रेस्तरां, पाली हिल्स में सी व्यू पैलेस में फ्लैट और जुहू के इक्विेस्ट बिल्डिंग में एक विला, जुहू में चार मंजिला रॉयल रेनबो, लिवस्मार्ट प्रोजेक्ट कुर्ला में 1,000 करोड़ रुपये के बिना बिका 570 फ्लैट और भांडुप में 150 करोड़ रुपये का ड्रीम मॉल शामिल है। कुछ अन्य संपत्तियों में ईसीआर चेन्नई में 15-20 एकड़ जमीन, पुणे में एक प्लॉट, मैसूर में होटल कंट्री इन, पुणे में रेडिसन ब्लू, महाबलेश्वर में चार एकड़ जमीन और एक बंगला और खंडाला के डेल्ला रिसॉर्ट्स में एक प्लॉट शामिल है।

पूछताछ के दौरान ईडी ने पाया कि डीएचएफएल ने कुछ छद्म फर्मों की मदद से अपने शेयर की कीमतों में कई मौकों पर गड़बड़ी की। सूत्रों ने कहा, हाउसिंग फाइनैंस ने कुछ इकाइयों को कागज पर कर्ज का आवंटन किया, जिसने बाद में कंपनी के शेयर थोक में खरीदे ताकि शेयर कीमतों में गड़बड़ी की जा सके।

एसयूवी के बाजार में होगा दंगल

नई क्रेटा का अनावरण करते हुंडई मोटर्स के एमडी व सीईओ एस एस किम और अभिनेता शाहरुख खान (बाएं)। मारुति सुजूकी ने ऑटो एक्सपो में विटारा ब्रेजा के पेट्रोल संस्करण का अनावरण किया। फोटो : संजय शर्मा

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 6 फरवरी

किसी वक्त छोटी कारों के लिए मशहूर भारत आज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) का गढ़ बन गया है और कंपनियां इस मैदान में दंगल तेज करने जा रही हैं। मारुति सुजूकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा और रेनो इंडिया जैसी स्थापित कंपनियों को अभी तक किया मोटर्स और चीन की मॉरिस गैराजेस (एमजी) से ही टक्कर मिल रही थी, लेकिन अब फोक्सवैगन इंडिया और ग्रेट वॉल मोटर ने भी एसयूवी बाजार में उतरने का ऐलान कर दिया है।

हुंडई मोटर इंडिया ने ऑटो एक्सपो के पहले दिन बुधवार को प्रीमियम एसयूवी तुसों का नया मॉडल दिखाने के बाद आज क्रेटा को भी बदले हुए रूप में पेश कर दिया। मारुति सुजूकी इंडिया ने भी अपने इकलौते एसयूवी विटारा ब्रेजा का नया संस्करण आज पेश किया। लेकिन फोक्सवैगन इंडिया ने भी भारत में चार नई एसयूवी लाने का ऐलान कर इन कंपनियों से होड़ के अपने मंसूबे जाहिर कर दिए।

फोक्सवैगन फिलहाल भारत में एसयूवी नहीं बेचती है। लेकिन अगले 24 महीनों में वह चार एसयूवी उतारेगी। फोक्सवैगन पैसेंजर कार्स के सेल्स ऑपरेशंस प्रमुख आशिष गुप्ता ने कहा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त एसयूवी ही सबसे तेजी से बिक रही हैं। दुनिया में बिकने वाली 30 फीसदी गाड़ियां एसयूवी होती हैं और अगले पांच साल में आंकड़ा 45 फीसदी होने की उम्मीद है। भारत में भी कहानी कमोबेश ऐसी ही है, इसलिए फोक्सवैगन यहां एसयूवी का अपना बेड़ा उतारने जा रही है।

कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइगुन, टिगुआन, टिगुआन ऑलस्पेस और टी-रॉक उतारेगी, जिनमें 7 सीट वाली टिगुआन ऑलस्पेस टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को टक्कर देगी। टाइगुन से कंपनी को ज्यादा उम्मीद होगी क्योंकि यह सबसे तेजी से बढ़ रहे कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में उतरेगी। गुप्ता ने संकेत दिया कि इसकी कीमत क्रेटा और सेल्टॉस के आसपास रहेगी। फोक्सवैगन भारत से इस गाड़ी का निर्यात भी करेगी।

फोक्सवैगन अगले 24 महीनों में भारत में उतारेगी चार एसयूवी

क्रेटा की होड़ में सेल्टॉस उतारने वाली किया मोटर्स अब सॉनेट के साथ हुंडई वेन्यू, फोर्ड ईकोस्पोर्ट और विटारा ब्रेजा से टकराने जा रही है। कंपनी के मार्केटिंग एवं सेल्स प्रमुख मनोहर भट्ट ने बताया कि गाड़ी इसी साल उतारी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसे उतारने के साथ ही आंध्र प्रदेश स्थित किया संयंत्र तीनों पालियों में काम करने लगेगा और सालाना 3 लाख गाड़ियों के उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगा।

किया की सेल्टॉस बेहद सफल रही है और अगस्त 2019 से अभी तक कंपनी इसकी 60,000 इकाइयां बेच चुकी है। पिछले महीने भारतीय बाजार में 15,000 से अधिक सेल्टॉस बिकी थीं। इसीलिए कंपनी एसयूवी बाजार पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। भट्ट ने कहा कि हैचबैक या सिडैन उतारने में भी कंपनी को परहेज नहीं है, लेकिन भारत में सिडैन का बाजार बहुत सुस्त है, इसलिए कंपनी एसयूवी पर ही जोर दे रही है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो में ही लिमोजिन कार्निवल भी पेश की है। एसयूवी बाजार की स्थापित खिलाड़ी भी पीछे रहने को तैयार नहीं हैं। तुसों और क्रेटा के नए संस्करण उतारने के बाद हुंडई इंडिया के प्रबंध निदेशक एसएस किम ने कहा कि नए खिलाड़ियों का आना अच्छी बात है, लेकिन वेन्यू से लेकर तुसों तक हरेक श्रेणी के एसयूवी होने के कारण हुंडई को किसी तरह की चिंता नहीं है। हुंडई भारत में बनी क्रेटा की पांच लाख से अधिक इकाइयां बेच चुकी है और वेन्यू की बिक्री के आंकड़े भी बहुत अच्छे रहे हैं। किम ने कहा कि कंपनी जरूरत के मुताबिक एसयूवी उत्पादन बढ़ाएगी और नए मॉडल पेश करने में भी पीछे नहीं रहेगी।

एसयूवी बाजार की देसी दिग्गज टाटा मोटर्स ने भी एक्सपो में 4 मीटर से कम लंबाई वाली एचबीएक्स एसयूवी दिखाई, जो इसी साल त्योहारी मौसम में पेश होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार के मार्केटिंग प्रमुख विवेक श्रीवत्स ने कहा कि बेहतर डिजाइन और फीचर वाली छोटी एसयूवी के ग्राहक हर छोटे-बड़े शहर में बढ़ रहे हैं और कंपनी उनकी मांग पूरी करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इसकी कीमत के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन माना जा रहा है कि कीमत के मामले में यह मारुति इग्निस और महिंद्रा की केयूवी 100 के आसपास होगी।

बर्ड ने उतारी किफायती ई-कार

ऋषभ कृष्ण सक्सेना
नई दिल्ली, 6 फरवरी

अगले साल आएगी 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार

भारत की कंपनी बर्ड इलेक्ट्रिक ने आज चीनी कंपनी हाइमा न्यू एनर्जी के साथ मिलकर किफायती इलेक्ट्रिक कार ईवी1 पेश कर दी। कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया, लेकिन इसे 10 लाख रुपये से कम दाम में ही लाया जाएगा। बर्ड ग्रुप की सहायक बर्ड इलेक्ट्रिक के कार्यकारी निदेशक अंकुर भाटिया ने बताया कि कार की बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है और 2021 के अंत में ग्राहकों को कार मिलने लगेगी। कंपनी मानेसर में संयंत्र लगाने की तैयारी में है और चीन से पुर्जों की शक्ल में यानी सीकेडी के रूप में लाकर कार को यहां असेंबल किया जाएगा। लेकिन उसके साल भर के भीतर कंपनी इसे भारत में ही बनाने की कोशिश करेगी, जिसके लिए अलग-अलग वेंडरों से बात की जा रही है।

ईवी1 एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलेगी और कंपनी इसे बेचने के लिए ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों से भी बात कर रही है। कंपनी इसके बाद ई-सिडैन भी पेश करेगी। इससे देश में इलेक्ट्रिक कार के बाजार में होड़ बढ़ सकती है क्योंकि चीन की ग्रेट वॉल मोटर भी 8-9 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार आर1 भारत में उतारने की तैयारी कर रही है।

किया मोटर्स को भारत में दमदार बिक्री की आस

शैली सेठ मोहिले और
अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 6 फरवरी

किया मोटर्स इंडिया को भारतीय बाजार में मौजूदा सुस्ती और एसयूवी बाजार में प्रतिस्पर्धा के बावजूद दमदार बिक्री होने का भरोसा है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। तगड़ी प्रतिस्पर्धा वाले भारत के यात्री कार बाजार में हाल में कदम रखने वाली इस कंपनी अपने सेल्टोस और कार्निवल मॉडलों के लिए दमदार ऑर्डर बुकिंग से उत्साहित है।

हाल में उतारे गए प्रीमियम बहुउद्देशीय वाहन कार्निवल की कीमत 24 लाख रुपये से 33.94 लाख रुपये के दायरे में है। किया मोटर्स इंडिया के प्रमुख (बिक्री एवं विपणन) मनोहर भट्ट ने कहा कि 21 जनवरी को इसके लिए बुकिंग शुरू होने के बाद अब तक ऑर्डर बुकिंग 1,410 वाहनों से बढ़कर 3,500 वाहनों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, 'कार्निवल को मिली प्रतिक्रिया

से हम काफी खुश और अचंभित हैं।' उन्होंने बताया कि करीब 70 फीसदी बुकिंग टॉप एंड मॉडल के लिए है। भट्ट ने दावा किया कि कंपनी लिमोसिन डिजाइन मॉडल के साथ एक नई श्रेणी सृजित कर रही है।

सीटों की विभिन्न व्यवस्था के साथ उपलब्ध आठ सीटों वाले टॉप एंड मॉडल में दो लोगों के सोने के लिए पर्याप्त जगह वाली सीट हैं। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट स्टार्ट स्टॉप आदि तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।

इसके ग्राहकों का प्रोफाइल मिश्रित है। भट्ट ने कहा कि पूरे परिवार के लिए आरामदायक वाहन की तलाशने वाले लोग भी इसके ग्राहक हैं। बाजार में कार्निवल मुख्य तौर पर महिंद्रा अल्टुरास, इनोवा क्रिस्टा आदि को टक्कर देगी।

आईएचएस मार्किट के सहायक निदेशक पुनीत गुप्ता ने कहा कि इस श्रेणी में कुछ ही मॉडल होने के कारण बाजार में काफी संभावनाओं का भुनाया जाना अभी बाकी है।

इस बीच, किया का प्रमुख वाहन सेल्टोस की बुकिंग अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इसे पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। भट्ट ने कहा कि फिलहाल 30,000 वाहनों बुकिंग के लिए आपूर्ति करना बाकी है और इसके लिए प्रतीक्षा अवधि ढाई से तीन महीने की है।

किया मोटर्स ने अपने बिक्री नेटवर्क को मौजूदा 240 आउटलेट से बढ़ाकर इस साल के अंत तक 300 आउटलेट करने की योजना बनाई है।

बीएस बातचीत

'ई-वाहनों पर बदलेंगे ग्राहकों की सोच'

ऑटो शो के पहले दिन मारुति ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह फिलहाल भारतीय बाजार के हिसाब से ई-वाहनों की व्यवहार्यता में भरोसा नहीं रखती। हालांकि दूसरे दिन टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्याधिकारी **गुंटेर बट्सचेक** ने **अरिंदम मजूमदार** के साथ साक्षात्कार में कहा कि उनकी कंपनी और मारुति में अंतर है और मारुति केवल कीमतों पर ध्यान देती है। संपादित अंश:

ऑटो शो अपनी वैश्विक पहचान खो रहा है और कंपनियां नए वाहन लॉन्च करने के लिए ही इसका उपयोग कर रही हैं। हालांकि आपने यहां भव्य मंच सजाया है। इसकी वजह?

वैश्विक चर्चाओं के पीछे बजट, ग्राहकों पर पड़ने वाला प्रभाव जैसे कई कारक काम करते हैं। आज के समय ग्राहक उत्पाद के बजाए समाधान आधारित शो की उम्मीद करते हैं। विशेष तौर पर इस ऑटो शो में कंपनियों की संख्या घटने के पीछे आर्थिक मंदी प्रमुख कारण है। मंदी के कारण कार्यक्रम में जाने के लिए अधिकांश कंपनियों में आंतरिक चर्चाएं हो रही हैं। भारत हमारे लिए घरेलू बाजार है और हमारे मंच पर उत्पाद तथा समाधान के साथ ही विद्युतीकरण पर काफी जोर दिया गया है। मंदी शुरू होने पर हमें लगा कि यह कुछ समय के लिए होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 18 महीने हो गए हैं और सरकार से प्रोत्साहन राशि की जरूरत है। सरकार ने ढांचागत उपायों के साथ बजट में भी कई प्रस्ताव किए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

क्या मांग में तेजी के लिए ये उपाय काफी होंगे?

विदेशी होने के नाते इस पर विचार व्यक्त करने के लिए मैं सबसे सही व्यक्ति नहीं हूं। आप सरकार की बाधाओं को समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। बजट में घोषित उपायों का असर दिखने में समय लगेगा। हम बीएस-4 से बीएस-6 की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। बीएस-4 को लेकर लोगों के बीच फैला भ्रम एक अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।

भारतीय बाजार की अगुवा मारुति ने ई-वाहनों पर धीमी गति से बढ़ने का निर्णय लिया है। आपने काफी तेज कदम उठाए। क्या आप भारतीय बाजार को दूसरे नजरिये से देख रहे हैं?

मेरा मानना है कि मारुति तथा हमारे बीच काफी अंतर है। मारुति हमेशा ग्राहकों के बीच प्रासंगिक बने रहने के लिए कीमतों पर काफी ध्यान देती है। हमारा मानना है कि उद्योग में निवेश लाने के लिए ई-वाहनों की जरूरत होगी जिससे आखिरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ेगी।

क्या भारतीय कीमतों के बजाए पारदर्शिता के बारे में सोचेंगे?

मैं इस मामले में ग्राहकों की सोच को महत्त्वपूर्ण नहीं मानता और मैं इसे बदल सकता हूं। हम टाटा संस ग्रुप का अहम हिस्सा हैं। प्रवर्तक निवेश कर रहे हैं लेकिन हम ग्रुप को वापस देने के बारे में क्या सोचते हैं? चार वर्ष पहले समूह में शामिल होते समय हमने तीन वर्ष में पूरी तरह तैयार हो जाने का लक्ष्य रखा था। तीन वर्षों में सभी चुनौतियों का समाधान कर लिया गया। नए उत्पाद के साथ कीमतें कम करने तथा गुणवत्ता सुधारने पर काम किया गया।

रिजर्व बैंक से मिला वक्त

रियल एस्टेट व छोटे उद्यमों को मिली मदद

सुब्रत पांडा और नम्रता आचार्य
मुंबई/कोलकाता, 6 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज के एकमुश्त पुनर्गठन की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है, जो 31 मार्च, 2020 को खत्म होने जा रही थी। कर्जदाता संपत्ति के वर्ग के फिर से वर्गीकरण किए बगैर एमएसएमई के कर्ज का पुनर्गठन कर सकेंगे।

साथ ही मौजूदा दौर में संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) को शुरू करने की तारीख का भी विस्तार किया है। यह सुविधा उन मामलों में मिलेगी जहां परियोजना में देरी प्रवर्तकों की वजह से नहीं हुई है। इस सुविधा को संपत्ति वर्गीकरण को घटाए बिना एक साल के लिए बढ़ाया गया है।

एमएसएमई कर्ज के पुनर्गठन विंडो को विस्तार बजट घोषणा के बाद दिया गया है, जिसमें वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था कि वह एमएसएमई कर्ज के पुनर्गठन विंडो की अवधि मार्च 2021 तक बढ़ाए, जो अभी मार्च 2020 है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए पुनर्गठन विंडो से पिछले एक साल के दौरान 5 लाख एमएसएमई को मदद मिली है।

रिजर्व बैंक ने कहा है, '... यह फैसला किया गया है कि संपत्ति के वर्गीकरण को घटाए बगैर एकमुश्त पुनर्गठन के लाभ को विस्तार की सुविधा जीएसटी में पंजीकृत उन एमएसएमई खातों को दिया जाए, जहां चूक 1 जनवरी 2020 तक हुई है। इस योजना के तहत पुनर्गठन 31 दिसंबर 2020 तक किया जा सकेगा।'

रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए विंडो से कर्जदाता एमएसएमई कर्ज का फिर से वर्गीकरण बगैर उनका पुनर्गठन कर सकेंगे, जिन मामलों में चूक 1 जनवरी 2020 तक हुई है। इसके पहले रिजर्व बैंक ने संपत्ति के वर्गीकरण को घटाए बगैर एकमुश्त पुनर्गठन की सुविधा उन कर्ज के लिए दी थी, जिनमें चूक 1 जनवरी 2019 तक हुई है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इसमें एक शर्त भी लगाई है। पुनर्गठन विंडो का लाभ उन्हीं एमएसएमई को मिलेगा, जो वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुनर्गठन योजना जीएसटी पंजीकरण की शर्त के बगैर आती तो पुनर्गठन वाले कर्ज की मात्रा बहुत ज्यादा होती।

यूनियन बैंक आफ इंडिया के एमडी और सीईओ अशोक कुमार प्रधान ने कहा, 'जो एमएसएमई एनपीए बनने के कगार पर हैं, उन्हें बचा लिया गया है।'

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'एमएसएमई के कर्ज के पुनर्गठन की तिथि बढ़ाने से उस क्षेत्र को भी मदद मिलेगी, जो मौजूदा कारोबारी सुस्ती की मार झेल रहे हैं और यह बजट घोषणा के मुताबिक है।'

रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में नवंबर के आखिर तक सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में कर्ज की वृद्धि दर ऋणात्मक -3.4 प्रतिशत रही है। मझोले उद्यमों के मामले में यह 03.6 प्रतिशत रही है।

जहां तक बगैर संपत्ति वर्गीकरण को घटाए वणिज्यिक रियल एस्टेट के परियोजना ऋण के डीसीसीओ के एक साल के विस्तार का सवाल है, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डेवलपरों को परियोजनाएं पूरी करने में कुछ मदद मिलेगी, जो नकदी के संकट की वजह से अटक गई हैं। कुमार ने कहा, 'परियोजना ऋण के डीसीसीओ को एक साल और विस्तार दिए जाने से रियल एस्टेट क्षेत्र को परियोजना पूरी करने पर ध्यान देने का मौका मिलेगा।'

इस कदम का लाभ डेवलपरों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) दोनों को ही मिलेगा। रिजर्व बैंक द्वारा राहत की घोषणा किए जाने के बाद एचएफसी के शेयर तेजी से बढ़े। इंडिया बुलल्स हाउसिंग फाइनैंस का शेयर 15.3 प्रतिशत बढ़ा। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस के शेयर क्रमश: 8.2 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत चढ़े हैं।

रिजर्व बैंक ने बढ़ाया हाथ

- एमएसएमई के लिए कर्ज के एकमुश्त पुनर्गठन की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है, जो 31 मार्च, 2020 को खत्म होने जा रही थी
- पुनर्गठन विंडो का लाभ उन्हीं एमएसएमई को मिलेगा, जो वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) को शुरू करने की तारीख का भी विस्तार दिया गया
- इससे फंसी परियोजनाओं पर काम करने में डेवलपरों को मिलेगी मदद

मौद्रिक नीति की प्रमुख बातें

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए बढ़ाकर 5.0 से 5.4 फीसदी के बीच कर दिया गया है जबकि दिसंबर की मौद्रिक नीति में इसके 3.8 से 4.0 फीसदी रहने का अनुमान था
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए घटाकर 5.5 से 6 फीसदी कर दिया गया है, जबकि इसके पहले की मौद्रिक नीति में 5.9 से 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था
- नकदी प्रबंधन ढांचे में संशोधन किया गया है जिसमें भारित औसत कॉल दर को परिचालन लक्ष्य के रूप में चिह्नित किया गया है
- मौद्रिक पारेषण में सुधार के लिए दीर्घावधि रीपो परिचालन की गणना पाक्षिक आधार पर की जाएगी
- नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कुछ छूट की अनुमति देकर उत्पादक क्षेत्रों को कर्ज बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन दिया गया है
- बैंकों द्वारा मझोले उद्यमों को फ्लोटिंग रेट पर दिए जाने वाले कर्ज की बाह्य बेंचमार्किंग बढ़ाई गई
- वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों के लिए एकमुश्त कर्ज पुनर्गठन योजना की मियाद बढ़ाई गई
- परियोजना ऋण का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने में एक साल की देरी की मंजूरी का प्रावधान
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार-पे, भीम ऐप और पीओएस टर्मिनलों का इस्तेमाल कर मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक के रूप में काम करने को अनुमति

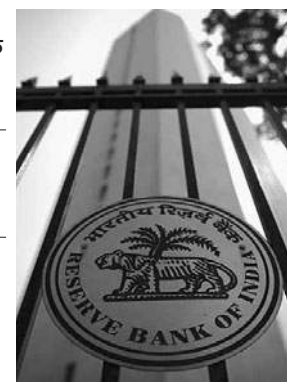

- आवासीय वित्त कंपनियों के लिए फरवरी के अंत तक आ सकता है संशोधित नियम मसौदा
- भारत में सक्रिय विदेशी इकाइयों सहित रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव से संबंधित सभी लेनदेन के लिए खाता खोलने का प्रस्ताव
- ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव के रूपांतरण मार्जिन की अदला-बदली के लिए दिशानिर्देश जारी करने का फैसला
- जुलाई 2020 से डिजिटल भुगतानों से जुड़े ब्योरे के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लाया जाएगा
- डिजिटल भुगतान के लिए स्व-नियामक संगठन बनाने का प्रस्ताव
- सितंबर 2020 से चेक खंडन व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी
- रीपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है। इससे पहले फरवरी से दिसंबर, 2019 के दौरान केंद्रीय बैंक ने रीपो दर में कुल मिलाकर 1.35 प्रतिशत की कटौती की थी
- चीन में कोरोना वायरस शुरू होने और दुनिया के विभिन्न देशों तक इसके फैलने का वैश्विक पर्यटन और व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था पर इस संक्रामक बीमारी के प्रसार के आर्थिक प्रभावों से निपटने से निपटने के लिए आकस्मिक योजना तैयार रखी जानी चाहिए
- केंद्रीय बैंक की बढ़ते राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अधिक रुपया छापने की केंद्रीय बैंक की कोई योजना नहीं
- रिजर्व बैंक ने कहा है कि जमा बीमा पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से बैंकों के बही खाते पर असर नहीं पड़ेगा

व्यवस्था में नकदी

रिटेल, एमएसएमई को 2 लाख करोड़ अतिरिक्त

अभिजित लेले और नम्रता आचार्य
मुंबई/कोलकाता, 6 फरवरी

एमएसएमई उधारी और बढ़ी खुदरा उधारी में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने को लेकर छूट देने से बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज देने और ब्याज दरें 15 आधार अंक घटाने में मदद मिलेगी।

बैंकरों का कहना है कि खुदरा कर्ज, सीआरआर की राहत और नकदी बढ़ाने से बैंकों को खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र पर ऐसे समय में ज्यादा ध्यान देने में मदद मिलेगी, जब कॉर्पोरेट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कर्ज की मांग कम है। यह भी उम्मीद है कि इन कदमों से बैंकों को बाजार में नकदी के संकट से जूझ रही वित्त कंपनियों व हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों द्वारा खाली की गई जगह को भी भरने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वाणिज्यिक बैंक जनवरी के अंत तक के बकाया कर्ज के ऊपर खुदरा व एमएसएमई क्षेत्र के बढ़े कर्ज के बराबर की राशि नकद आरक्षित अनुपात बरकरार रखने के लिए जमा की जाने वाली राशि में से कम कर सकते हैं। यह छूट 31 जुलाई 2020 तक बढ़े कर्ज के लिए उपलब्ध रहेगी।

रिजर्व बैंक ने दीर्घावधि रीपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) के तहत कदमों की घोषणा की है, जिससे मौद्रिक प्रेषण में सुधार हो सके और बाजार की स्थिति को देखते हुए स्थिर नकदी उपलब्ध हो सके। उपयुक्त आकार की एक साल और तीन साल की अवधि के लिए कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये की सावधिक खरीद-फरोख्त सुविधा की घोषणा की गई है। यह खरीद-फरोख्त रिजर्व बैंक की रीपो दर पर होगी। इस सुविधा को 15 फरवरी से शुरू होने वाले पखवाड़े से शुरू कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक एक लाख करोड़ रुपये की राशि के एक साल और तीन साल की रीपो दर पर किए जाने वाले खरीद- बिक्री समझौतों का फैसला मौद्रिक नीति का लाभ आगे ग्राहकों तक पहुंचाने की बेहतरी के लिए किया गया है। इस समय नीतिगत रीपो दर 5.15 प्रतिशत है।

बैंकिंग क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि सीआरआर में कटौती से बैंकों को पूरी व्यवस्था में 5,000 करोड़ रुपये तक बचाने में मदद मिलेगी, जो ग्राहकों को दिया जा सकता है. बैंकों का आवास ऋण 13 लाख करोड़ रुपये और वाहन ऋण 2 लाख करोड़ रुपये का है। यह क्षेत्र क्रमश: 17.6 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं।

बदली नीति

नकदी ढांचे में बदलाव, रोजाना रीपो विंडो खत्म

अनूप रॉय
मुंबई, 6 फरवरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नया नकदी प्रबंधन ढांचा स्वीकार किया है। इसमें रोजाना तय नकदी नहीं डाली जाएगी, बल्कि केंद्रीय बैंक ऐसा तभी करेगा जब बैंकिंग व्यवस्था में धन की जरूरत होगी और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा चुका होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वेटेड एवरेज कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि वह पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा और रीपो रेट पर मुख्य ध्यान होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कॉल रेट रीपो रेट से ऊपर जाती है तो यह नकदी की कमी का संकेत होगा और केंद्रीय बैंक नकदी डालने के साधनों का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से अगर कॉल रेट रीपो रेट से कम होगा तो इसका मतलब यह है कि बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी है। ऐसे में रिजर्व बैंक नकदी कम करने का काम करेगा। नकदी प्रबंधन गलियारा 50 आधार अंक पर बरकरार रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि रिजर्व बैंक कॉल रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी (एमएसएफ) रेट (इस समय 5.40 प्रतिशत) और रिवर्स रीपो रेट (इस समय 4.90 प्रतिशत) तक बढ़ने देगा, जबकि रीपो रेट मध्य में 5.25 प्रतिशत बना रहेगा।

बीएस बातचीत

मौद्रिक नीति का असर पड़े, इस पर केंद्रित है रिजर्व बैंक की कवायद

नीति समीक्षा बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर **शक्तिकांत दास** और डिप्टी गवर्नर **एन एस विश्वनाथन, माइकल देवव्रत पात्र** और **बीपी कानूनगो** ने मीडिया से एलटीआरओ (दीर्घ अवधि रीपो परिचालन) शुरू करने और आने वाले दिनों में दर में कटौती करने की संभावना सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मुख्य अंश...

गुरुवार को मुंबई में संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, ईडी जनक राज, गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो और डिप्टी गवर्नर एमडी पात्र (बाएं से दाएं) *फोटो- कमलेश पेडणेकर*

आपने 1 लाख करोड़ रुपये की दीर्घ अवधि रीपो परिचालन (एलटीआरओ) पेश किया है और इन्क्रीमेंटल रिटेल क्रेडिट के लिए बैंकों को सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) में छूट दी है। क्या यह एक प्रकार की छिपी हुई ब्याज दर कटौती है?

शक्तिकांत दास: मूल रूप से मौद्रिक नीति के प्रभावी रूप से काम करने के लिए एक प्रयास है। क्योंकि हम इसे नीति दर पर दे रहे हैं। लिहाजा, हम 1 लाख करोड़ रुपये जो बैंकिंग प्रणाली में डालना चाहते हैं उससे बैंक अपने ऋण दरों को घटाने में सक्षम हो पाएंगे।

क्या एलटीआरओ ओएमओ (खुला बाजार परिचालनों) का स्थान लेगी? साथ ही, सूचकांकों पर भारतीय बॉन्डों को शामिल करने के बारे में कोई ब्योरा देंगे?

दास: दीर्घ अवधि रीपो परिचालानों का उद्देश्य ओएमओ की जगह लेना नहीं है। दरअसल, एलटीआरओ का विचार बैंकों के लिए ऑन-लेंडिंग (तीसरे पक्ष को ऋण देने) के लिए किसी तरह से फंडों की लागत में कमी लाना है। यही वजह है कि इसे रीपो दर पर रखा गया है। साथ ही, इससे उन्हें अपने पास टिकाऊ नकदी होने का भरोसा मिलता है जिससे बैंकों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए खासकर तब जब वे यह देख रहे हैं कि जमा दरें नीचे की ओर मजबूत बनी हुई है।

बजट घोषणा में कहा गया है कि कुछ निश्चित सरकारी बॉन्ड में गैर-आवासीय भागीदारी के संबंध में कोई सीमा नहीं है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है कि अब हम उच्च विदेशी निवेश को स्वीकार कर सकते हैं, उच्च विदेशी पूंजी का इस्तेमाल अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं लेकिन उसका प्रवाह रुपयों के संबंध में होगा न कि डॉलर के संबंध में। काफी हद तक विदेशी बचतों का उपयोग घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जिससे सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू बचतों पर दबाव भी कम हुआ है।

आप कह रहे हैं कि महंगाई के दबाव के कारण दरें नहीं घटा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त तरलता बनी हुई है और दिसंबर से फरवरी के बीच आपने ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया था। ऐसे में मौद्रिक समीक्षा का व्यापक स्वरूप क्या है जिसपर आप काम कर रहे हैं और ऑपरेशन ट्विस्ट से आप क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे थे?

दास: बेहतर मौद्रिक नीति बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त तरलता जरूरी है क्योंकि हमारे 135 आधार अंकों के होने के बावजूद वहां पर्याप्त तरलता होनी जरूरी है। इसलिए केवल जून से व्यवस्था में उचित तरलता की स्थिति बनी। ऑपरेशन ट्विस्ट एक ऐसा जरिया है जिसका इस्तेमाल बेहतर मौद्रिक नीति बदलाव को सुनिश्चित करने में किया जाता है।

तीन साल के रीपो से बदलाव में सुधार आने की उम्मीद है। क्या होगा यदि कोई बैंक 5.15 फीसदी की दर पर रिजर्व बैंक से उधार लेता है और एक साल बाद आप ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं तो क्या बैंक उन दरों का बोझ आगे ग्राहकों पर डालने में सक्षम होंगे? एफआरबीएम अधिनियम के तहत एक बार बदलाव किए जाने पर सरकार उनके घाटे का भी मुद्रीकरण कर सकती है, ऐसे में क्या है आपके लिए चिंता की बात है?

दास: फिलहाल सरकारी घाटे के मुद्रीकरण की कोई योजना नहीं है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.8 फीसदी हो जाने के बावजूद उधारी में वृद्धि उसी स्तर पर बनी हुई है और अगले वर्ष में यह वृद्धि महज 70,000 करोड़ रुपये की है। यदि इसकी गणना जीडीपी के प्रतिशत के तौर करें तो यह चालू वर्ष की उधारी से कम है।

एनएस विश्वनाथन: यह तरलता प्रबंधन की बात है जिस पर हम काम कर रहे हैं। बैंकों को तीन साल के ब्याद दर परिदृश्य को लेकर सचेत रहना होगा। लेकिन फिलहाल हम यह देख रहे हैं कि यदि बैंक केवल रात भर के लिए उधार लेते हैं तो यह रिवर्स रीपो में हमारे पास रातोंरात वापस आ जाता है। लिहाजा, हम चाहते हैं कि वे लंबी अवधि के लिए उधार लें जो ऋण के तौर पर जाएगी।

माइकल पात्र: ये तीन साल का रीपो मौजूदा 5.15 फीसदी की चालू नीति दर पर दी जाएगी।

बीएस सूडोकू 3658

परिणाम संख्या 3657

		5						2
2						1		
		8	3		2	9	4	
			9	7				
	4			3			2	
				6	1			
	9	3	1		8	5		
		6						1
8						3		

8	7	5	1	4	2	3	9	6
9	2	4	3	5	6	8	1	7
1	3	6	7	9	8	5	2	4
2	6	3	8	1	7	9	4	5
4	8	1	5	6	9	2	7	3
5	9	7	4	2	3	6	8	1
7	1	9	2	3	5	4	6	8
3	4	2	6	8	1	7	5	9
6	5	8	9	7	4	1	3	2

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल ★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2010/2020, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4250/4300, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1450/1550,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1355, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1428, फ्लैक 1375, डीएमओ 983, टरपीन लैस बोल्ड 1452

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1050/1150, खुरपा 980/1020,चाकू 1050/1100, रसकट 900/910, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3250,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/970, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4250, खल: सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2350, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1800/1810, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3775/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4325/4350,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3750/3800, जौ 2100/2125,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7000/7100, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1825/1835, चना 4000/4100, काबली चना 5000/6000, मूंग 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)107, राइसब्रान (अखाद्य) 104, खल सरसों 1900, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1000, लाल 1020, कंटीन्यूअस 1150,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9800, छिलका 8700/9300, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5800/5900, सेला 5250/5300, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4000/4050,चावल 1509 सेला 4950/5000, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4050/4090, हरियाणा 4030/4050, राजस्थान 4000/4050, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2000/2010,

फाजिल्का
गेहूं 2030/2040, सरसों 4150/4200 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2020/2050, चावल परमल कच्चा 2325/2365, से ला 2260/2310, मक्की यूपी 2100/2120, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4700/4750, दाल चना 5100/5150, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7500/8900,चीन 8500/9000, शर्मिली 6000/7300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2015/2030, बासमती चावल 6300/6400, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2600/2640, शरबती धान 2050/2100, सेला (1509 नं.) चावल 4950/4975, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, जौ 1840/1850, सरसों 3900/3950, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/480, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2150/2250, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8750/8800, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1700/1750 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 303

दरों में कटौती से इतर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बाजार के अनुमानों के मुताबिक ही नीतिगत दरों को अपरिवर्तित छोड़ने का निर्णय लिया है। मुद्रास्फीति का जो परिदृश्य सामने आ रहा है, उसने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में 7.4 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई। जबकि सब्जियों, खासकर प्याज की कीमतों में दिसंबर की उछाल से गिरावट आने की संभावना है। मुद्रास्फीति में गिरावट निकट भविष्य में दालों और अन्य प्रोटीन उत्पादों की बढ़ी कीमतों के आधार पर थम सकती है। दूरसंचार कीमतों में समायोजन भी मूल मुद्रास्फीति पर लागत का दबाव डाल रहा है। हालांकि यह चार फीसदी के इर्दगिर्द बना हुआ है।

एमपीसी ने कहा है कि भविष्य में कदम उठाने के लिए नीतिगत गुंजाइश बरकरार है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति घटकर 3.2 फीसदी हो जाएगी। हालांकि काफी अनिश्चितता भी है। यदि मुद्रास्फीति में आरबीआई के अनुमान के मुताबिक कमी आती है तो वह नीतिगत दरों में 25 आधार अंक की कमी कर सकता है। उस स्थिति में रीपो दर 4.9 फीसदी हो जाएगी। मौद्रिक नीति के माध्यम से वृद्धि का इससे अधिक सहयोग करना मुश्किल होगा। यदि अनुमान से अधिक अवस्फीति होती है तो शायद कुछ गुंजाइश बन सकती है। ऐसा कोरोनावायरस के कारण वैश्विक वृद्धि में धीमापन आने से हो सकता है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। चूंकि भविष्य में मौद्रिक राहत की गुंजाइश सीमित है इसलिए केंद्रीय बैंक अब पारेषण और ऋण बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उदाहरण के लिए उसने वाहन, आवास और सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को ऋण देने के मामले में बैंकों को 30 जुलाई, 2020 तक नकद आरक्षित अनुपात बरकरार रखने में राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने एमएसएमई के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना भी बढ़ा दी है तथा वाणिज्यिक अचल संपत्ति में परिसंपत्ति वर्गीकरण को शिथिल किया है। आरबीआई ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मझोले उपक्रमों को दिए जाने ऋण का बाह्य मानकीकरण करने का भी निर्णय लिया है। यह अगले वित्त वर्ष के आरंभ में शुरू किया जाएगा। इन हस्तक्षेपों के अलावा केंद्रीय बैंक एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि की रीपो की व्यवस्था करेगा। करीब एक लाख करोड़ रुपये की इस राशि से बैंकिंग तंत्र में अधिक पैसा आएगा और ऋण दरों में कमी आएगी। लंबी अवधि के बॉन्ड और बैंक ऋण दर के मामलों में मौद्रिक पारेषण धीमा रहा है। मसलन 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड के मामले में प्रतिफल 76 आधार अंक तक घटा जबकि नीतिगत दर में 135 आधार अंक की कमी की गई।

कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को जो नीतिगत हस्तक्षेप घोषित किए हैं उनके पीछे इरादा पारेषण में सुधार लाने और बैंकिंग प्रणाली को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने का है। परंतु इन उपायों से ऋण में सुधार होगा या नहीं यह देखना होगा। उदाहरण के लिए बाह्य मानक से बैंकों के ब्याज मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालांकि घोषणा के बाद प्रतिफल में कमी आई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि लंबी अवधि की रीपो किस हद तक बैंकिंग तंत्र की मददगार रहेगी। ध्यान रहे करीब 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य की नकदी तरलता मौजूद है। दीर्घावधि की दरें, उच्च सरकारी उधारी और घटती घरेलू बचत के कारण एक खास दायरे में रह सकती हैं। अब सरकार अनिवासी निवेशकों के लिए विशेष प्रतिभूतियों की घोषणा करके बचत का आयात करना चाहती है। इससे मुद्रा की लागत कम करने में मदद मिलेगी लेकिन इससे केंद्रीय बैंक के नकदी और मुद्रा प्रबंधन के लिए चुनौती उत्पन्न हो सकती है।

अजय मोहंती

बजट को कोसने के बजाय करें आकलन

बाजार के लिए बजट निराशा लेकर आया, लेकिन प्रश्न यह है कि पिछले छह वर्षों में पेश लचर बजट के बावजूद कारोबारी समुदाय ने सातवीं बार कुछ अजूबा होने की उम्मीदें क्यों पाल रखी थीं? बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

शनिवार तक उद्योगपतियों और वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बात को लेकर लगभग एकमत थे कि वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में देश को आर्थिक रफ्तार देने के लिए कुछ नए एवं बड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे। बाजार भी बजट से ऐसी ही उम्मीदें लगाए बैठा था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स अक्टूबर के करीब 38,000 स्तर से उछलकर जनवरी के तीसरे सप्ताह में 42,000 के स्तर तक पहुंच गया। बजट को लेकर उत्साह उस पत्र में शायद सबसे बेहतर ढंग से जाहिर किया गया था, जो मुझे बजट से दो दिन पहले एक कारोबारी सलाहकार ने भेजा था। उस सलाहकार ने पत्र के माध्यम से अपनी टिप्पणी में कहा था, '2020 को कई वर्षों तक इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि भारत में किसी तरह चीजें एक झटके में बदल गईं। 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट वह क्षण हो सकता है।' फंड प्रबंधक आकाश प्रकाश ने इसी समाचार पत्र के अंग्रेजी संस्करण में लिखा था कि बजट से लीक से हटकर और सही मायनों में सुधारवादी कदमों की उम्मीदें हैं। बजट में देश के बिखरे आर्थिक ताने-बाने को एकजुट करने के लिए सरकार द्वारा पेश प्रस्तावों के ढाई घंटे बाद सेंसेक्स लगभग 1,000 अंक नीचे फिसल गया। हालांकि मैं बाजार की तत्काल प्रतिक्रिया को अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं देख रहा, लेकिन इसने उस पहलू को जरूर सही सिद्ध किया, जिस ओर मैं इशारा करना चाह रहा हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरा इशारा बजट में आर्थिक वृद्धि दर को मजबूती देने के लिए ठोस उपाय नदारद रहने से उपजी निराशा की तरफ है।

आम राय पर सवाल

मेरे मन में यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर बजट को लेकर इतनी उम्मीदें पालने का आधार क्या था? आखिर इतने कुशल, पेशेवर और सफल लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पिछले छह बजट से निराशा हाथ लगाने के बाद भी उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सातवीं बार कुछ अजूबा होने जा रहा है? इसका सरल जवाब है: खोखली उम्मीद या जान बूझ कर सच की अनदेखी करने से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मौजूदा स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं, लेकिन एक खोखली बुनियाद के भरोसे सच्चाई की अनदेखी भी बड़ी सहजता से की जा सकती है।

इससे पहले पिछले छह वर्षों में एक के बाद एक बजट से निकल कर आईं चीजों की लोगों ने जान बूझकर अनदेखी की। लोगों ने कठोर कानून, आर्थिक तंत्र कमजोर करने वाली आर्थिक नीतियां, सरकार का जरूरत से अधिक हस्तक्षेप, कारोबारियों एवं नागरिकों के लिए अधिक परेशानियां, नए उपायों के लिए सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता, अधिक पेचीदा कानून एवं नियम, आर्थिक अनुसार, 'हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां दूसरा कोई विकल्प नहीं (नो अदर ऑप्शन या एनओसी) नहीं है। एनओसी का समय आ गया है। एक गौरवमयी विरासत छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए सफलता का स्वाद चखना जरूरी हो गया है। उनके दूसरे कार्यकाल में 2020 एक अति महत्त्वपूर्ण समय है। मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी केंद्रीय टीम की मदद से व्यक्तिगत तौर पर सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले नरसिंह राव ने पर्दे के पीछे रहकर मनमोहन सिंह के माध्यम से सुधार को आगे बढ़ाया। यह अलग बात रही कि उस समय आर्थिक सुधारों का सारा श्रेय मनमोहन सिंह को मिल गया।'

यह एक खोखले विश्वास का आधार था, जिसे मान लिया गया, लेकिन जिसका आकलन कभी नहीं किया गया। एक दृढ़ निश्चयी, कठिन परिश्रमी और एक शानदार विरासत छोड़ने की तमन्ना रखने वाले प्रधानमंत्री में वाकई अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से निकालने की क्षमता है! आखिर कई बुद्धिमान लोगों ने इस अवधारणा पर भरोसा ही क्यों किया? हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिल्बर्ट ने लिखा है, 'लोगों में अक्सर किसी बात पर तुरंत विश्वास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही उनके लिए किसी चीज को शक के नजरिये से देखना भी मुश्किल होता है। वास्तव में विश्वास करना इतना आसान और अवश्यंभावी है कि लोग तर्कों पर कसने के बजाय स्वत: ही चीजें स्वीकार कर लेते हैं।' गिल्बर्ट और उनके सहयोगियों ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है कि लोग अक्सर उन चीजों को पहली नजर में सही मान लेते हैं, जो वह पढ़ते हैं सुनते हैं। अगर हम लोगों की विश्वास करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सुश्री हेफरनैन द्वारा आंकड़ों में हेरफेर पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा और सरकार के भटकाने वाले नारे एवं बयानों में उलझ कर रह गए। इन सभी चीजों से देश गंभीर आर्थिक संकट की तरफ बढ़ गया।

तेज एवं सफल लोग, जो अरबों रुपये निवेश कर वास्तविक जीवन के निर्णय लेते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और मन में यह मुगालता पाल लिया कि यह बजट कुछ अलग साबित होगा। ऐसी नौबत क्यों आई? जैसा कि मार्ग्रेट हेफरनैन अपनी किताब 'विलफुल ब्लाइंडनेस' में लिखती हैं, 'हम हरेक चीजों पर नजर नहीं रख सकते और न ही हरेक बातें जान सकते हैं। हमें चीजें तलाशनी होती है और इनमें आवश्यक बदलाव करने होते हैं। इस तरह, हम किस पहलू का चयन करते हैं किस बात की अनदेखी करते हैं यह बात काफी अहम हो जाती है। ज्यादातर मामलों में हम उन बातों को पसंद करते हैं, जिनसे हम अच्छा अनुभव करते हैं और हमारा अहं संतुष्ट होता है। हम उन चीजों को दरकिनार कर देते हैं, जिन्हें स्वीकारना हमारे लिए मुश्किल होता है। वैचारिक नजरिया और रूढ़िवादिता उन बातों सामने आने नहीं देती हैं, जो एक स्वतंत्र मस्तिष्क आसानी से भांप कर सतर्क हो सकता है। हमारे इर्द-गिर्द भी ऐसा माहौल पनपने लगता है, जो हमें सच्चाई की अनदेखी करने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है।'

कारोबारी सलाहकार की टिप्पणी के प्रतिपादित तथ्यों को सुविधानुसार छांटने के सिद्धांत से जोड़कर देखें तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह बजट से खोखली उम्मीदें लगाई गई थीं। फंड प्रबंधक, कारोबारी, सलाहकार सभी की ख्वाहिश थी कि बजट में वृद्धि दर को मजबूती देने के उपाय किए जाएं। ऐसी चाह रखने में उनके अपने हित जुड़े थे और इसमें उनका यह विश्वास भी था कि उनके दूरदर्शी नेता आखिर में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। कुल मिलाकर सरकार के काम-काज के तरीकों से इतर उन्होंने अपने दिमाग में अपने हिसाब से उम्मीदें पाल लीं।

आखिर में एक और अहम बात पर मेरी नजर जाती है। 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और माइकल स्टीनहार्ड्ट दो शीर्ष निवेशक हुआ करते थे। सोरोस कारोबारी थे, जबकि स्टीनहार्ड्ट निवेशक थे। दोनों का मानना था कि आप उस समय तगड़ा मुनाफा कमाते हैं जब आप देखते हैं कि पूरा बाजार एक ऐसी चीज में विश्वास कर रहा है, जो पूरी तरह आधारहीन है। बस इसके लिए आपको इस मानसिकता के उलट दांव खेलना होता है। वारेन बफेट ने इसी चीज को दूसरे तरीके से परिभाषित किया। उनके अनुसार आप अगर एक खुशनुमा माहौल में शामिल होने की एक बड़ी कीमत चुकाते हैं। शनिवार को पेश बजट उन तेज तर्रार दिमाग वालों के लिए एक बड़ी सीख दे गया, जो बिना किसी पुख्ता आधार वाली उम्मीदों की सवारी कर रहे थे।

तेजी से बढ़ता जा रहा है भारत का मनोरंजन उद्योग

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

सामग्री एवं विषय-वस्तु की बढ़ती उपलब्धता से भारतीय मनोरंजन उद्योग कारोबार को खासी मजबूती मिल रही है। दिल्ली के लाजपत नगर में भूतल में बने एक छोटे से कार्यालय में विषय-वस्तु की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता का एक मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। राहुल भाटिया के बिजनेस ऑफ लैंग्वेजेज (बीओएल) के तीनों छोटे स्टूडियो में बिना रुके लगातार काम चल रहा है। पहले पर्दे (स्क्रीन) पर नैशनल ज्योग्रेफिक डॉक्युमेंट्री का हिंदी रूपांतरण हो रहा है, वहीं दूसरे कमरे में अंग्रेजी में लिखी एक पटकथा का हिंदी में अनुवाद हो रहा है। तीसरे कमरे में एक चर्चित वॉइस आर्टिस्ट शब्दों का रियाज कर रही है। मुझे बताया गया कि वह लोकप्रिय बाल किरदार शिनचेन के लिए अपनी आवाज देती है।

औसतन बीओएल हरेक महीने 100 घंटे से अधिक की सामग्री अंग्रेजी, चीनी, जापानी और स्पैनिश भाषा से हिंदी, तमिल, तेलुगू सहित अन्य भारतीय भाषाओं में रूपांतरित करती है। करीब दो वर्ष पहले हरेक महीने 20 घंटे की सामग्री के विभिन्न भारतीय भाषाओं में रूपांतरण पर काम हो पाता था। उस समय उन 20 घंटे में करीब 16 घंटे की सामग्री टेलीविजन के लिए तैयार होती थी। अब ये आंकड़े बीते दिनों की बात हो चुके हैं। 100 घंटे में करीब आधी सामग्री टेलीविजन के लिए, 30-40 घंटे ओटीटी और शेष सामग्री इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सर्विसेज के लिए होती हैं।

अगर आप 'द प्रोटेक्टर', 'ट्रोलहंटर्स' (नेटफ्लिक्स) या 'इट्स नॉट दैट सिंपल' (वूट) या 'परमानेंट रूममेट्स' (टीवीएफ) सहित अन्य कार्यक्रमों पर ध्यान दें तो इनके लिए बीओएल को श्रेय दिया जाता है। दिल्ली के दूसरे इलाकों या चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में भी ऐसी कई कंपनियां दिख जाएंगी, जो प्रोडक्शन बाद की गतिविधियों या डबिंग का काम करती हैं। सामग्री सृजन में आई जबरदस्त तेजी का सबसे पहला खुशनुमा प्रभाव यह हुआ है कि इससे उन सभी चीजों की मांग बढ़ी है, जिनकी मदद से 'सैक्रेड गेम्स' या 'द फैमिली मैन' जैसे कार्यक्रम पूरी दुनिया में लाखों टीवी, मोबाइल और अन्य उपकरणों तक पहुंच पाते हैं।

ये सामग्री विभिन्न भाषाओं सहित तकनीकी सेवाओं और अन्य माध्यमों के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं। इस जबरदस्त बदलाव का एक दूसरा असर यह हुआ है कि प्रतिभाओं की पूछ बढ़ी है और इनका मूल्यांकन भी खासा बढ़ा है। एक तीसरा अहम बदलाव यह हुआ है कि इससे भारत में 1,67,400 करोड़ रुपये के मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में युवा एवं मध्य स्तर पर प्रतिभाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान अधिक दिया जाने लगा है। पहले प्रतिभाओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। गूगल, एमेजॉन, एटीऐंडटी, डिज्नी, कॉमकास्ट, ऐपल और नेटफ्लिक्स सहित दूसरी कंपनियां दर्शकों का अपने साथ जोड़ने के लिए दुनिया भर में नए कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। इससे किसी भी देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश की सामग्री अपनी भाषा में देख सकता है। उदाहरण के लिए भारत में लोग नार्कोज (स्पैनिश, कोलंबिया), फ्रांस के लोग सैक्रेड गेम्स (हिंदी, भारत) या तुर्की के लोग डार्क (जर्मन, जर्मनी) सहित अन्य देशों के लोग दूसरे देशों के कार्यक्रम अपनी भाषा में देख सकते हैं। दर्शकों की यह खोज इन कंपनियों को भारत की तरफ खींच लाई है। भारत एक ऐसा बाजार है, जहां इन कंपनियों को दर्शकों के साथ ही कहानी कहने वाले भी मिल जाते हैं। कोरिया के बाद भारत उन कुछ बाजारों में शुमार है, जहां स्थानीय स्तर पर सामग्री मौजूद हैं और यहां एक बाजार भी है, जो इन सामग्री का प्रस्तुतीकरण बेहतर ढंग से करता है। 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय जो कुछ सुनते या देखते हैं वह स्थानीय होता है।

अब दुनिया भर में इस चलन को तवज्जो दी जा रही है। जुलाई 2018 में एक हिंदी कार्यक्रम 'सैक्रेड गेम्स' दुनिया के 190 देशों में नेटफ्लिक्स के 12.5 करोड़ उपभोक्ताओं के बीच दिखाया जाने लगा। करीब एक साल से अधिक समय बीतने के बाद सितंबर 2019 में 'लस्ट स्टोरीज' (नेटफ्लिक्स) और 'द रीमिक्स-इंडिया' (एमेजॉन प्राइम वीडियो) कार्यक्रमों सहित 'सैक्रेड गेम्स' इंटरनैशनल एमी अवार्ड्स के लिए नामित किए गए। उन्हें सफलता भले ही नहीं मिली, लेकिन 'सैक्रेड गेम्स' द न्यू यॉर्क टाइम्स के दशक के 30 इंटरनैशनल सीरीज की सूची में जगह बनाने में सफल रहा। एमेजॉन प्राइम वीडियो के अनुसार भारतीय कार्यक्रम देखने वाले इसके प्रत्येक तीन दर्शकों में एक भारत से बाहर के हैं। कलाकार, निर्देशक से लेकर लेखक तक भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा रहा है और इसमें हैरान होने की बात भी नहीं है। वर्ष 2018 में शीर्ष 10 ओटीटी पर वास्तविक सामग्री की अवधि बढ़कर करीब 400 घंटे हो गई, जो 2016 में महज 20 घंटे हुआ करती थी। 2019 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 1,000 घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में औसतन 1,600 से अधिक फिल्में बनती हैं और यह दुनिया में फिल्म निर्माण करने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन यह ओहदा हासिल करने के बाद भी विभिन्न भाषाओं एवं विभिन्न सोच रखने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त 500 उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में तैयार करना एक अहम चुनौती है।

भाटिया कहते हैं, 'पिछले एक वर्ष में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के लिए भारतीय कंपनियों की तरफ से काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता रही है।' कई पात्रों के साथ कहानियों के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज भी एक दूसरा मसला है। इससे निपटने के लिए अगस्त 2019 में भाटिया ने स्कूल ऑफ लर्निंग (एसओएल) की शुरुआत की। नेटफ्लिक्स भी अपनी तरफ से इस ओर थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है। अक्टूबर 2019 में इसने विजुअल ऐंड स्पेशल इफेक्ट्स, साउंड, म्यूजिक, वर्कफ्लो सहित विभिन्न विषयों पर चार दिवसीय एक पोस्ट प्रोडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया। नेटफ्लिक्स के इस कार्यक्रम में 30 से अधिक काम करने वाले पेशेवरों ने भाग लिया। कुल मिलाकर भारत का सृजनात्मक क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है।

कानाफूसी

कितनी गंभीर है कांग्रेस?

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो वह हर वर्ष स्थानीय बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषण से निपटने और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने में व्यय करेगी। लेकिन पार्टी ने चुनाव प्रचार में जो विज्ञापन छापे हैं उनमें यह आंकड़ा 20 फीसदी दर्शाया गया है। इतना ही नहीं कई और बिंदुओं पर भी अंतर देखने को मिला है। पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि जे जे कॉलोनी के किरायेदारों और मालिकों समेत हर परिवार को उसी स्थान पर 350 वर्ग फुट का फ्लैट प्रदान किया जाए। जबकि होर्डिंग तथा अन्य विज्ञापनों में पार्टी ने 269 वर्ग फुट के फ्लैट देने का वादा किया है। घोषणापत्र में 15,000 इलेक्ट्रिक बसों का वादा किया गया है जबकि विज्ञापन में यह संख्या 10,000 बताई गई है। तिपहिया चालकों और ई-रिक्शा के बारे में विज्ञापन में कहा गया है कि वह सत्ता में आने पर ऐसे तमाम ऋण माफ कर देगी। लेकिन घोषणापत्र में ऐसे वाहनों के मालिकों को एकबारगी सब्सिडी देने की बात कही गई है। घोषणापत्र में सरकारी स्कूलों में भाषा शिक्षकों की रिक्तियां 100 दिन के भीतर पूरी करने का वादा किया गया है। वहीं विज्ञापन में 11,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही गई है। इसमें भाषा शिक्षक भी शामिल हैं। परंतु इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। क्या वाकई पार्टी राज्य में सरकार बनाने को लेकर गंभीर है?

आपका पक्ष

असम में समझौते के बाद बढ़ेगा निवेश

असम में 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देश के अन्य हिस्सों (बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर आदि) से बड़ी संख्या में मजदूरों को चाय बागानों में काम करने के लिए बसाया गया। यह इस क्षेत्र के स्थानीय समुदायों में असंतोष का एक बड़ा कारण बना। इसके बाद से ही लगातार बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसा होती रही तथा एक अलग बोडोलैंड की मांग की जाने लगी। इस समस्या का समाधान मोदी सरकार ने निकाल लिया है। इससे स्थानीय स्तर पर शांति स्थापित होगी और विकास का काम तेजी से बढ़ेगा। समझौते में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस समझौते में असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन 'नैशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड' के साथ बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े अन्य संगठनों के

असम में 19वीं सदी के मध्य में अन्य राज्यों से लोग चाय बागान में काम करने गए थे

सदस्य भी शामिल हुए। समझौते के तहत सभी पक्षकारों ने अलग बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बजाय असम राज्य के अंतर्गत ही स्वायत्त बोडोलैंड क्षेत्र की व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई। इस समझौते के अनुसार नई व्यवस्था में बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत चार जिलों के स्थान पर सात जिले दिए गए। इस समझौते के माध्यम से बोडो जनजाति के विकास के साथ असम की आतंरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक अस्थिरता के समाधान के लिए यह समझौता बहुत ही महत्त्वपूर्ण साबित होगा। क्षेत्रीय अस्थिरता इस क्षेत्र में निवेश के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई थी। इस समझौते से पूर्वोत्तर भाग में निवेश को बल मिलेगा।

अनु मिश्रा, सीवान

चुनाव घोषणापत्रों में प्रलोभन अधिक

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी बड़े दल अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। अगर चुनावी घोषणा पत्रों पर नजर डालें तो आरंभ में इसमें पार्टी की संपूर्ण राजनीतिक कार्यप्रणाली एवं विचारधारा को प्रकट किया जाता था। उन्हीं राजनीतिक कार्यप्रणाली एवं विचारधारा के आधार पर दल चुनाव लड़ते थे। आज सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में विचारधारा का अंत हो गया है। उसका स्थान भौतिक वस्तुओं एवं प्रलोभन ने ले लिया है। एक विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी तक भी भौतिक वस्तुएं देने का प्रचलन शुरू कर चुकी है। सवाल यह उठता है कि चुनावी घोषणापत्रों में साइकिल, स्कूटी एवं लैपटॉप जैसी भौतिक वस्तुओं को क्यों शामिल करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने अपने घोषणापत्र में ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल देने की घोषणा की तथा चुनाव जीतने के बाद अपना वादा पूरा किया। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ता था। वहां सरकारी एवं निजी परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन दिल्ली में छात्राओं को स्कूटी देने का वादा कितना उचित है जबकि यहां सार्वजनिक परिवहन सेवा बस, मेट्रो आदि दुरुस्त है। चुनावी घोषणा पत्र में भौतिक वस्तुओं को शामिल करने से क्या वास्तव में देश का भला होगा। इस पर सभी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

ज्ञान रंजन मिश्रा, आरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

संक्षेप में

बीते साल चाय निर्यात तीन प्रतिशत घटा

बीते साल चाय का निर्यात मामूली घटकर 24.82 करोड़ किलोग्राम रह गया। चाय बोर्ड के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले साल चाय का निर्यात 25.60 करोड़ किलोग्राम रहा था। बीते साल हालांकि, चाय निर्यात का मूल्य बढ़कर 5,610.65 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 2018 की तुलना में 275 करोड़ रुपये अधिक है। चाय बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि चाय निर्यात में कमी की वजह देश से कुछ निर्यात में गिरावट आना है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय चाय के प्रमुख खरीदारों में सोवियत संघ से अलग हुए देशों का समूह यानी सीआईएस देश शामिल हैं। सीआईएस ने पिछले साल 5.91 करोड़ किलोग्राम भारतीय चाय का आयात किया था। यह 2018 के 6.3 करोड़ किलोग्राम से कम है। ब्रिटेन को भी चाय का निर्यात घटकर 1.17 करोड़ किलोग्राम रह गया, जो 2018 में 1.57 करोड़ किलोग्राम था। पाकिस्तान को निर्यात 62.3 लाख किलोग्राम रहा, जो इससे पिछले साल 1.58 करोड़ किलोग्राम था। हालांकि, ईरान की वजह से चाय निर्यात का आंकड़ा ज्यादा नीचे नहीं गया है। ईरान ने 5.34 करोड़ किलोग्राम भारतीय चाय का आयात किया जो इससे पिछले साल 3.07 करोड़ किलोग्राम रहा था। *भाषा*

कृष्णापुरम प्याज निर्यात को कुछ शर्तों के साथ अनुमति

सरकार ने कृष्णापुरम प्याज का कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति दे दी है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णापुरम इलाके का खास किस्म का प्याज है। सरकार ने केवल मार्च अंत तक की अवधि में इस किस्म की 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के निर्यात की अनुमति सिर्फ चेन्नई बंदरगाह के जरिये होगी। डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा, '10,000 टन तक कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह निर्यात 31 मार्च, 2020 तक किया जाना है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।' अपने छोटे आकार और तीखेपन की वजह से कृष्णापुरम प्याज का स्थानीय स्तर पर रसोई में अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन थाइलैंड, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर में इसकी अच्छी मांग है। *भाषा*

चावल निर्यात में आएगी कमी

अमेरिका-ईरान के गतिरोध और कोरोनावायरस से निर्यात पर पड़ेगा असर

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 6 फरवरी

चावल निर्यात

- इस साल भारत के चावल निर्यात में 18 से 20 प्रतिशत तक गिरावट के आसार
- वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईरान को 1.5 अरब डॉलर मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया गया था
- भारत के निर्यात में ईरान का वार्षिक योगदान 25 से 30 प्रतिशत रहता है
- नकारात्मक भू-राजनीतिक हालात, व्यापार के कड़े नियम और सरकार द्वारा एमएसपी में इजाफा किए जाने से चावल निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ा

अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध और चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप जैसे प्रमुख भू-राजनीतिक तथा घरेलू कारणों से इस साल भारत के चावल निर्यात में 18 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आने के आसार हैं। पिछले साल ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद खास तौर पर ईरान को बासमती चावल निर्यात में अनिश्चितता बनी रही है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईरान को 1.5 अरब डॉलर मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया गया था। भारत के निर्यात में ईरान का वार्षिक योगदान 25 से 30 प्रतिशत रहता है।

वर्ष 2010 और 2019 के बीच की अवधि में चावल निर्यात में करीब 14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है। नकारात्मक भू-राजनीतिक हालात, व्यापार के कड़े नियम और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इजाफा किए जाने से चावल निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर 25 प्रतिशत का योगदान करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। देश के कुल निर्यात बास्केट में इस जिंस का योगदान दो प्रतिशत रहता है।

अमेरिका की व्यापारिक वित्तीय कंपनी ड्रिप कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव की वजह से पश्चिम एशिया की ओर से बड़ी गिरावट आने के कारण इस साल चावल निर्यात में वैश्विक स्तर पर गिरावट देखी गई है। यह रिपोर्ट निर्यातकों के साथ की गई बातचीत और आंकड़ों के अलावा भारत की चावल की खेपों के विश्लेषण पर आधारित है। इन खेपों में बासमती चावल का प्रमुख हिस्सा रहता है।

ड्रिप कैपिटल के सह-संस्थापक और सह-मुख्य कार्याधिकारी पुष्कर मुकेवर ने कहा कि इस साल अब तक खेपों में 22 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए सबसे बड़े निर्यात बाजार ईरान के साथ निर्यात फीका नजर आ रहा है। मुंबई स्थित चावल करोबारी और निर्यातक देवेंद्र वोरा ने कहा कि अमेरिका-ईरान संकट में कोई राहत नहीं मिलने की वजह से अक्टूबर 2019 से चावल का निर्यात नरम रहा है। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि ईरान को किया जाने वाला वार्षिक निर्यात एक करोड़ टन रहता है और इस क्षेत्र में खेपों में लगभग 20 लाख टन तक की गिरावट आने की प्रबल संभावना है। जिन भारतीय करोबारियों ने स्टॉक रोका हुआ है, उन्हें नुकसान होने की आशंका है।

इस बीच कोहिनूर फूड्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक गुरनाम अरोड़ा ने कहा कि चूंकि ईरान भारतीय चावल निर्यात का प्रमुख गंतव्य है, इसलिए निर्यात में कमी के रूप में इसका असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक धारणा को देखते हुए मुझे इस साल चावल निर्यात में 20 प्रतिशत गिरावट नजर आ रही हैं। कोरोनावायरस के प्रकोप से इस धारणा पर दबाव और बढ़ गया है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुस्ती के रूप में दिख रहा है। उनके अनुसार भारतीय चावल के लिहाज से कई अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पिछले कई महीनों से गिरावट चल रही है।

वर्ष 2016 से 2019 के दौरान तीन प्रतिशत सीएजीआर के साथ भारत के शीर्ष बासमती चावल निर्यातक राज्य हरियाण ने वित्त वर्ष 19 में अकेले ही 241 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था। वित्त वर्ष 19 में 110 करोड़ डॉलर के निर्यात के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2016 से 2019 के दौरान इस राज्य ने 47 प्रतिशत की प्रभावशाली सीएजीआर दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश इस निर्यात में योगदान करने वाले अन्य प्रमुख राज्य हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ब्राजील के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर सरकार मामले को ठीक से आगे बढ़ाती है, तो ब्राजील को लगभग 10 लाख टन चावल निर्यात की संभावना है जो चावल और गेहूं सहित खाद्यान्न का एक बड़ा उपभोक्ता है।

साल की शेष अवधि के मुकाबले कटाई के चार महीने बाद (दिसंबर-मार्च) की अवधि में वार्षिक निर्यात 40 प्रतिशत से अधिक रहता है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष के निर्यात में पिछले सालों के प्रदर्शन की तुलना में काफी नरम रख रहा है। ईरान के अलावा अन्य निर्यात बाजार यानी संयुक्त राज्य अरब अमीरात (33 प्रतिशत), नेपाल (23 प्रतिशत), यमन (दो प्रतिशत), सेनेगल (90 प्रतिशत) और बांग्लादेश (94 प्रतिशत) में भी चावल की खेपों में गिरावट नजर आई है। हालांकि सऊदी अरब (चार प्रतिशत), इराक (10 प्रतिशत), बेनिन (आठ प्रतिशत) और अमेरिका (चार प्रतिशत) जैसे देशों को किए जाने वाले चावल निर्यात में कुछ तेजी दर्ज हुई है।

इस साल फिर महंगी दाल बिगाड़ेगी घर का बजट!

सुशील मिश्र
मुंबई, 6 फरवरी

दाल की कीमतें इस साल भी आम लोगों का बजट बिगाड़ सकती है। मौसम के बिगड़ने से दलहन फसलों की पैदावार प्रभावित हुई है जिसका असर इनकी कीमतों पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने कच्चे तेल की कीमतों में उथलपुथल जारी रहने के बीच दूध और दालों के भाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया है। दलहन कारोबारी पहले ही पैदावार में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जता चुके हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि आने वाले समय में महंगाई दर पर खाद्य महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और सेवाओं की लागत जैसे कई कारकों का असर होगा। रिजर्व बैंक ने खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर कहा है कि दिसंबर के उच्च स्तर की तुलना में इसमें नरमी आने का अनुमान है। खरीफ फसल के विलंब से आने तथा रबी फसल की आवक के कारण प्याज की कीमतें सुधर रही हैं। अत: चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी अधिक स्पष्ट दिखेगी। केंद्रीय बैंक ने एक तरफ पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनावों तथा दूसरी तरफ अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण कच्चे तेल में उथलपुथल बने रहने की आशंका जताई है। रिजर्व बैंक के अनुसार हाल के महीनों में सेवा लागत में वृद्धि देखने को मिली है।

रिजर्व बैंक ने अपनी तिमाही बैठक में रीपो दर को 5.15 फीसदी पर यथावत रखा है। उसने कहा कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए तथा 2020-21 में उत्तरी-पश्चिमी मॉनसून के सामान्य रहने के अनुमान के मद्देनजर खुदरा महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 2019-20 की मार्च तिमाही में 6.5 फीसदी, 2020-21 की पहली दो तिमाहियों में 5.4-5 फीसदी और 2020-21 की तीसरी तिमाही में 3.2 फीसदी किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सब्जियों को छोड़ अन्य खाद्य पदार्थों विशेषकर लागत बढ़ने से दूध की कीमतें तथा खरीफ उत्पादन कम रहने से दाल के दाम बढ़ने का अनुमान है।

दलहन कारोबारी इस साल उत्पादन कम होने की आशंका जता चुके हैं। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) की रिपोर्ट के अनुसार इस बार केंद्र ने 263 लाख टन दलहन पैदावार का लक्ष्य रखा था, लेकिन खराब मॉनसून से पैदावार में करीब 10 फीसदी की गिरावट आएगी। मूंग की पैदावार में करीब 30 फीसदी और उड़द की पैदावार करीब 50 फीसदी कमी आने का अनुमान है। आईपीजीए के बिमल कोठारी कहते हैं कि देश में दाल की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ानी ही होगी इसके लिए सरकार को आयात में ढील देनी होगी।

देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं जिससे देश में उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में 231.3 लाख टन, 2017-18 में 254.2 लाख टन की बंपर पैदावार हुई जबकि 2018-19 पैदावार थोड़ी गिरकर 231.2 लाख टन रही। एक दशक पहल भारत में दाल का औसत सालाना उत्पादन 140 से 180 लाख टन था। वर्ष 2015-16 में दाल के दाम बेतहाशा बढ़े थे। पिछले कुछ महीनों में सभी दालों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से अबतक देश में दालों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा उड़द दाल के दाम 40 फीसदी से भी ज्यादा बढ़े हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत में (30 सितंबर, 2019) देश में उड़द दाल का औसत भाव 6,350 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 6 फरवरी को बढ़कर 9,100 रुपये पहुंच गया। इस दौरान मूंग दाल 5,100 रुपये से 23.8 फीसदी बढ़कर 9,150 रुपये प्रति क्विंटल, तुअर दाल 7,900 रुपये से 13.9 फीसदी बढ़कर 8,300 रुपये क्विंटल, मसूर दाल 8.8 फीसदी बढ़कर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल और चना दाल करीब सात फीसदी बढ़कर 5,450 रुपये क्विंटल पहुंच गई।

दाल के दाम में बढ़ोतरी

दाल	30 सितं.	6 फर.	बढ़त (%)
उड़द	6,350	9,100	40.2
मूंग	7,350	9,150	23.8
तुअर	7,900	8,300	13.9
मसूर	5,100	5,950	8.8
चना	5,200	5,450	6.7

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 6	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,688.0	-7.1	1,980.3	4.9
Copper	5,714.0	-3.4	6,334.3	2.9
Nickel	13,005.0	-20.7	13,764.0	-19.6
Lead	1,843.5	-13.8	2,106.7	-2.2
Tin	16,335.0	-0.5	17,486.0	0.9
Zinc	2,222.5	-12.1	2,486.0	-9.0
Gold ($/ounce)	1,565.3*	5.0	1,762.1	5.1
Silver ($/ounce)	17.8*	0.8	20.2	1.0
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	54.8*	-11.7	53.9	-13.1
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-35.0	1.9	-34.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	196.6	8.1	291.4	-4.7
Maize	184.2*	1.5	264.5	-9.3
Sugar	415.8*	22.7	491.9	0.1
Palm oil	690.0	11.7	1,165.7	21.7
Rubber	1,344.0*	-6.8	1,882.0	6.0
Coffee Robusta	1,272.0*	-3.3	1,811.8	-5.1
Cotton	1,502.7	7.0	1,597.8	-0.4

* As on Feb 6, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	41.2	36608
Oil and Oilseeds	319.2	70792
Spices	0.7	10
Metal(Feb 05)		
Metal- non ferrous	6567.9	42828
Metal- precious	11461.0	388
Oil and gas(Feb 05)		
Gas	2308.6	50749
Oil	20594.4	2648

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	181.1	132258
Grains	172.5	97910
Oil and Oilseeds	877.4	453295
Others	138.5	64660
Pulses	104.7	42815
Spices	45.4	21020

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Oil (Feb 19)	3680.0	2.7
Nickel (Feb 28)	964.5	1.9
Aluminium Mini (Feb 28)	137.4	1.4
Copper (Feb 28)	434.5	1.4
Zinc Mini (Feb 28)	173.7	1.3
Zinc (May 29)	175.5	1.2
Gold Mini (Feb 05)	40411.0	0.9
Losers (* % Change)		
Cardamom (Feb 14)	3575.0	-0.9
Crude Palm Oil (Feb 28)	763.8	-0.8
Natural Gas (Feb 25)	133.0	-0.5
Cotton (Feb 28)	19340.0	-0.4
Kapas (Apr 30)	1075.5	0.0

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1821.0	2.6
Jeera Unjha (Mar 20)	14015.0	1.3
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7029.0	1.2
Guar Seed 10 (Feb 20)	3970.0	1.1
Chana-Bikaner (Mar 20)	3916.0	0.2
Coriander-Kota (Apr 20)	6370.0	0.1
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5948.0	0.0
<B>Losers<$>(* % Change)		
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4027.0	-1.5
Soyabean Indore (Feb 20)	4120.0	-1.2
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	855.2	-1.1
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3882.0	-0.5
Barley Jaipur (Apr 20)	1714.0	-0.2

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1075.5	4.7
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19340.0	1.7
Zinc Mumbai (May 29)	175.5	0.1
Gold Ahm (Feb 05)	40411.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1197.4	-10.6
Lead Min Mumbai (Feb 28)	145.4	-5.3
Lead Mum (May 29)	147.5	-3.9
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3575.0	-3.9
Gold Petal-Mumbai (Feb 28)	3994.0	-1.3
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	173.7	-0.9
Silver Ahm (Mar 05)	45735.0	-0.9
Nickel Mumbai (Feb 28)	964.5	-0.9

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1942.0	4.0
Bajra-Delhi (Feb 20)	1942.0	2.2
Maize-Sangli (Feb 20)	1883.0	1.0
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5948.0	0.8
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3108.0	0.3
Moong-Merta City (Feb 20)	7678.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1714.0	-20.2
Jeera Unjha (Mar 20)	14015.0	-4.0
Soy Bean Indore (Feb 20)	4120.0	-2.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6370.0	-1.9
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	744.2	-0.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai	
Aluminium utensil scrap /kg	105	(106)
Aluminium ingots /kg	141	(144)
Brass sheet cutting /kg	325	(320)
Brass utensil scraps/kg	312	(305)
Copper heavy scrap /kg	420	(416)
Copper utensil scraps/kg	394	(392)
Copper wire bar /kg	451	(449)
Lead ingots /kg	150	(150)
Nickel Cathodes /kg	980	(975)
Tin slabs /kg	1245	(1235)
Zinc slabs /kg	177	(176)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai	
Bengal Deshi /Qtl	10236	(10236)
DCH - 32 /Qtl	11332	(11304)
Jaydhar /Qtl	9758	(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11107	(11079)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai	
Castor FSG /10kg	837	(837)
Castor Comm /10kg	827	(827)
Groundnut oil /10kg	1140	(1140)
Palm oil /10kg	840	(840)
Sunflower exp ref /10kg	870	(870)
Sunflower oil exp /10kg	830	(830)
Soyabean ref / 10kg	855	(855)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai	
Mumbai M-30 /Qtl	3382-3622	(3382-3602)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	51.29	(50.75)
Brent Crude (UK)	54.72	(55.02)
Brent Crude (WTI)	50.75	(50.75)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.86	(1.86)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	285.21	(291.27)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai	
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40336	(40049)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40498	(40210)
Silver.999/ kg	46155	(45510)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18848.65	18891.05
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.10	138.35
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1910.00	1900.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1875.70	1867.75
Barley Jaipur (N)	1 Q	2147.05	2148.75
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3720.00	3758.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3996.75	4026.20
Castor Seed-Kadi (N)	X	3977.50	3995.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4025.00	3992.85
Chana Delhi (N)	1 Q	4250.00	4214.05
Chana-Akola (N)	X	3975.00	3925.00
Coriander-Gondal (N)	X	6338.00	6307.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6365.65	6366.65
Coriander-Kota (N)	1 Q	6437.20	6493.15
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1841.90	1863.60
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1904.60	1915.45
Cotton-Kadi (N)	1 B	18979.20	18958.85
CPO-Kandla (M)	10 K	766.50	768.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	741.55	748.10
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	740.00	740.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	904.95	902.55
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1550.50	1548.60
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3455.55	3455.05
Gold Ahm (M)	10 G	40059.00	40406.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32176.00	32455.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4020.00	4048.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7070.00	7038.55
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3950.00	3937.90
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3840.00	3863.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1092.40	1091.75
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.65	103.15
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15000.00	15000.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14524.00	14596.30
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	850.55	845.90
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1012.90	1021.65
Kapas-Rajkot (N)	X	1012.30	1013.40
Lead Mum (M)	1 K	150.60	153.50
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1890.00	1850.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2170.00	2120.85
Maize-Erode (N)	X	1830.00	1806.65
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2170.00	2120.85
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2025.00	2025.00
Maize-Sangli (N)	X	1877.90	1864.55
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4700.00	4650.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7660.00	7665.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4334.00	4256.75
Nickel Mumbai (M)	1 K	973.20	973.10
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3177.00	3176.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	328.80	327.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33280.00	33000.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	841.25	837.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	760.00	775.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1910.65	1901.65
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5346.45	5357.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	820.00	830.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	870.20	871.50
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	866.35	868.05
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	865.00	870.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13400.00	13400.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13350.00	13350.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	45510.00	46143.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4188.00	4232.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4100.00	4100.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4297.55	4332.90
Soy Bean-Akola (N)	X	4229.00	4250.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33800.00	33700.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	868.60	871.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31300.00	31410.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31400.00	31710.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28460.00	28670.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3270.00	3265.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3404.75	3404.75
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3289.00	3288.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3466.65	3466.65
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3283.70	3283.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3152.50	3150.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5915.20	5900.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2206.65	2210.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2164.55	2175.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2165.00	2155.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2103.75	2120.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2180.00	2185.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5575.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5500.00	5550.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	176.25	175.30

* as on Feb 05, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19330, 19410, 19280, 19340	1952	303	27968
Mar 31	19570, 19660, 19550, 19620	1037	135	6679
Apr 30	19860, 19910, 19850, 19870	357	53	1088
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1781, 1830, 1766, 1821	24000	1748	38560
Mar 20	1797, 1848, 1783, 1837	58460	3849	67830
Apr 20	1824, 1872, 1808, 1863	4120	379	17770
May 20	1845, 1896, 1840, 1883	430	39	4650
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1070, 1076.5, 1070, 1075.5	528	111	868
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072.5, 1077.5, 1069, 1075.5	1069	551	3448
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1715, 1715, 1710, 1714	40	4	2170
May 20	1710, 1714, 1710, 1710	140	7	1920
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3928, 3984, 3900, 3970	12960	1577	32550
Mar 20	3968, 4030, 3942, 4014	29765	3389	59240
Apr 20	3996, 4054, 3984, 4048	650	98	1910
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3900, 3940, 3860, 3882	3120	341	9270
Mar 20	3916, 3964, 3880, 3898	6215	737	20460
Apr 20	3930, 3978, 3898, 3906	655	111	4745
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	766.7, 774, 760.4, 763.8	19720	1457	44390
Mar 31	757.1, 763.3, 750.1, 756.2	15790	1092	19850
Apr 30	754.3, 762, 747, 754.9	4000	317	6290
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1195.2, 1203.5, 1186.9, 1197.4	133.2	295	188.64
Mar 31	1185, 1195, 1185, 1193	18.36	42	69.84
May 29	1160.1, 1160.1, 1160.1, 1160.1	0.72	2	3.24
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4060, 4070, 4015, 4027	10900	893	8560
Apr 20	4115, 4128, 4061, 4070	14700	1126	16020
May 20	4129, 4135, 4081, 4105	1040	94	3640
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	861.8, 863.4, 854.4, 855.2	17730	1645	28550
Mar 20	847.8, 851, 841.4, 843.2	20230	2075	53015
Apr 20	841.8, 847.6, 839, 841	1210	182	5805
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4160, 4186, 4094, 4120	31720	3546	62090
Mar 20	4174, 4194, 4096, 4126	49070	5871	142705
Apr 20	4180, 4200, 4108, 4128	11970	1618	82625
May 20	4178, 4220, 4132, 4160	2520	379	15465
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6975, 7055, 6881, 7029	6140	842	11640
Mar 20	7039, 7140, 6963, 7115	12855	1659	51160
Apr 20	7130, 7225, 7070, 7156	735	84	1860
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3900, 3947, 3881, 3916	19510	1403	23050
Apr 20	3916, 3940, 3887, 3915	6230	526	14990
May 20	3945, 3978, 3930, 3959	1030	95	4660
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3600, 3620, 3550, 3575	0.6	5	4.5
Mar 13	3600, 3650, 3586, 3622.7	1.4	14	4.9
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6328, 6390, 6311, 6370	3290	256	7370
May 20	6335, 6385, 6335, 6359	30	3	750
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13950, 14040, 13895, 14015	756	235	2007
Apr 20	13700, 13835, 13660, 13795	645	182	1608
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5950, 6000, 5916, 5948	615	97	4820
Apr 20	5940, 5970, 5882, 5926	200	38	4340
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	137.25, 137.9, 136.75, 136.9	5024	3538	5403
Mar 31	138.1, 138.4, 137.3, 137.55	139	128	411
Apr 30	132.95, 132.95, 132.95, 132.95	1	1	1
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	435.5, 439.45, 434.1, 434.5	22262.5	7408	11415
Mar 31	439.6, 440.2, 435.65, 435.9	490	188	1170
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.5, 146.1, 144.85, 144.9	7462	4708	6572
Mar 31	146.5, 146.65, 145.6, 145.65	176	133	582
Apr 30	145, 149.35, 145, 147.2	2	2	-
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	961.6, 967.4, 956.6, 957.4	11986.5	7220	3069
Mar 31	961.4, 965.8, 956, 957	202.5	95	196.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	176.1, 176.15, 174.5, 175.7	4	4	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	174.2, 174.6, 171.4, 171.65	26988	15482	18041
Mar 31	175.1, 175.25, 172.5, 172.85	966	714	3027
Apr 30	174.5, 174.5, 173.2, 173.75	4	4	8
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40081, 40397, 40030, 40361	6.73	5649	17.12
Jun 05	40254, 40560, 40201, 40524	0.31	233	5.35
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32134, 32250, 32100, 32237	0	223	0.01
Mar 31	32095, 32269, 32095, 32258	0	53	0
Apr 30	32185, 32190, 32185, 32188	0	2	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40043, 40330, 39972, 40287	0.85	7500	0.84
Apr 03	40091, 40360, 40019, 40332	0.16	1364	0.29
May 05	40195, 40425, 40141, 40396	0.01	74	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3991, 4004, 3984, 4002	0	1135	0.01
Mar 31	4005, 4019, 4003, 4018	0	254	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45800, 46233, 45761, 46174	288.15	7959	269.31
May 05	46319, 46745, 46271, 46691	5.43	172	25.05
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45820, 46269, 45769, 46198	38	26733	27.28
Apr 30	46312, 46760, 46300, 46707	3.7	2697	6.49
Jun 30	46800, 47199, 46800, 47115	0.02	20	0.16
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45808, 46247, 45776, 46192	96.16	15611	49.25
Apr 30	46374, 46752, 46313, 46703	3.74	696	7.27
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	133.4, 135.7, 131.7, 132.3	86881mb	38472	50330mb
Mar 26	136.3, 138, 134.2, 134.8	3890mb	2355	5550mb
Apr 27	140.6, 141.9, 138.4, 139	221mb	152	283mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3689, 3719, 3631, 3643	22550bl	129172	3913bl
Mar 19	3720, 3743, 3656, 3669	625bl	5451	363bl
Apr 20	3740, 3754, 3724, 3739	1bl	6	4bl

सायं सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Name Exchange (Units) Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19290, 19440, 19270, 19300	4362	667	27632
Mar 31	19610, 19700, 19540, 19570	1390	249	6548
Apr 30	19800, 19920, 19800, 19880	446	34	940
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1069.5, 1077, 1068.5, 1072.5	580	104	996
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1072, 1077.5, 1068, 1071.5	1002	557	3412
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	752.7, 772, 752.7, 763.9	38520	2605	43610
Mar 31	748, 763.5, 745, 753.9	24840	1511	21460
Apr 30	742.7, 762, 740, 755.4	3480	266	4430
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	851, 867, 851, 858.6	26900	2748	30485
Mar 20	838.2, 856, 838.2, 844	33055	3358	49790
Apr 20	837, 851, 833.6, 838	5070	488	5405
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	135.9, 137.8, 135.4, 137.35	16915	11040	4887
Mar 31	136.95, 137.95, 136.3, 137.8	605	517	377
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	429.5, 436.4, 429.5, 434.5	44127.5	14709	9970
Mar 31	433.75, 437, 433.2, 435.7	670	261	1142.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.4, 146.3, 144.8, 145.35	16178	10691	6008
Mar 31	146.1, 146.8, 145.5, 146.1	362	329	561
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	966, 966.6, 953, 964.5	32863.5	20243	2016
Mar 31	958.6, 964, 951.4, 963.2	334.5	192	171
Zinc MCX(1 K)				
May 29	174.15, 177.8, 174.15, 175.45	7	7	15
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	172, 174.65, 171.4, 173.7	53130	31632	14859
Mar 31	173, 175.25, 172.15, 174.6	2348	1674	2797
Apr 30	173, 175, 173, 174.1	6	6	10
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40201, 40280, 40000, 40411	0.01	10	0
Apr 03	40108, 40298, 39900, 40200	13.49	11598	16.64
Jun 05	40288, 40461, 40071, 40338	0.81	657	5.18
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	31902, 32240, 31565, 32159	0.01	879	0.01
Mar 31	32050, 32175, 31936, 32118	0	137	0
Apr 30	32090, 32100, 32090, 32097	0	3	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40690, 40700, 40100, 40411	0	25	0
Mar 05	39938, 40228, 39820, 40146	1.92	16739	0.77
Apr 03	40111, 40268, 39890, 40169	0.32	2744	0.25
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	3979, 4000, 3974, 3994	0.01	2886	0.01
Mar 31	3993, 4020, 3992, 4010	0	910	0
Apr 30	4060, 4060, 4005, 4030	0	5	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45690, 46016, 45356, 45735	687	19011	259.23
May 05	46252, 46525, 45932, 46215	6.9	212	23.46
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45638, 46034, 45375, 45750	94.73	67751	27.3
Apr 30	46194, 46560, 45936, 46284	7.31	5577	6.78
Jun 30	46761, 47030, 46483, 46669	0.03	30	0.16
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45722, 46025, 45369, 45754	249.56	40011	41.41
Apr 30	46327, 46550, 45926, 46295	8.24	1535	7.21
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	133.7, 134.8, 130.6, 133	168576mb	78992	45308mb
Mar 26	137.1, 137.4, 133.8, 135.6	5391mb	3626	5185mb
Apr 27	141, 141.2, 138, 139.8	316mb	238	256mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3590, 3700, 3551, 3680	54945bl	308584	2336bl
Mar 19	3611, 3722, 3579, 3703	1680bl	13882	308bl
Apr 20	3640, 3730, 3614, 3716	3bl	28	4b

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

प्रदर्शनों से अराजकता की स्थिति

मोदी ने कहा कि जीएसटी उनके दिमाग की उपज है, प्रणव मुखर्जी को दिया था इसका सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का मौजूदा स्वरूप उनके ही दिमाग की उपज थी। उन्होंने कहा कि जीएसटी का सुझाव उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संप्रग के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को दिया था जिसमें उत्पादक राज्यों को ज्यादा तवज्जो देना शामिल था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रणव मुखर्जी से कहा था कि उत्पादक राज्यों के मुद्दों को हल करना चाहिए। बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन मुद्दों को हल किया और इसके बाद सभी राज्यों में जीएसटी को लागू किया जा सका।

वहीं संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को हवा देने के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार को कहा कि संसद एवं विधानसभा के निर्णयों का सड़कों पर विरोध एवं आगजनी तथा लोगों द्वारा कानूनों को स्वीकार नहीं करने से अराजकता की स्थिति पैदा होगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग जवाब देते हुए आगाह किया कि विधायिका के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों और आगजनी से अराजकता उत्पन्न हो सकती है, सभी को इससे चिंतित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में अलोकतांत्रिक गतिविधियों को छिपाने के प्रयास हो रहे हैं, इससे किसी को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सीएए एवं एनपीआर के खिलाफ एक काल्पनिक भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के लिए नुकसानदेह है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद दोनों सदनों ने इस धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

गुरुवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राज्यसभा में कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

इससे पहले मोदी ने कहा कि सीएए पर हो रहे प्रदर्शनों से देश ने देख लिया कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीएए से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मोदी ने सीएए को लेकर विपक्ष पर काल्पनिक भय पैदा करने का आरोप लगाया और उनके रूख को पाकिस्तान के रूख से जोड़ते हुए कहा कि ऐसी ही भाषा पाकिस्तान भी बोलता है।

नागरिकता कानून के संदर्भ में मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करते हुए कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि जो प्रभावित लोग भारत में बसने के लिए आए हैं, वो नागरिकता मिलने के अधिकारी हैं और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं हैं तो कानून में बदलाव होना चाहिए।'

लोकसभा में करीब 100 मिनट के अपने जवाब में मोदी ने कश्मीर, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के समाधान सहित विविध मुद्दों को रेखांकित किया। मोदी ने कहा कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्व-धर्म समभाव की है। उन्होंने घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिक्र करते हुए कहा, '19 जनवरी 1990 की उस काली रात में कुछ लोगों ने कश्मीर की पहचान को दफना दिया था।' सीएए को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'संविधान बचाने के नाम पर दिल्ली और देश में क्या हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है और देश की चुप्पी कभी न कभी रंग लाएगी।' कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण के जरिये देश को बांटने का आरोप लगाया था।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं पूरी जिम्मेदारी से देश की 130 करोड़ जनता को कहना चाहता हूं कि सीएए का हिन्दुस्तान के किसी नागरिक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे कोई और हो।' मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो कुछ भी हुआ, राजनीति के तराजू से तौलकर और आधे-अधूरे मन से किया गया जबकि उनकी सरकार ने समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दीर्घकालिक नीति के तहत काम किया जिससें अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी तथा वित्तीय घाटा एवं महंगाई स्थिर रही।

एजेंसियां/बीएस

अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा भारत

बीएस संवाददाता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के बढ़ते सामरिक और आर्थिक विस्तार वाले अफ्रीकी देशों में भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़े संबंधों को बढ़ाए जाने के संकेत दिए। सिंह ने गुरुवार को लखनऊ में आयोजित भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की अफ्रीकी देशों से साझीदारी उनकी प्राथमिकताओं और क्षमताओं के हिसाब से होगी और यह आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के साथ-साथ साइबरस्पेस को सुरक्षित रखने पर भी केंद्रित होगी। उन्होंने कहा, 'भारत अफ्रीकी देशों को निगरानी पोत, इंटरसेप्टर बोट, नाइट विजन चश्मे, मानवरहित एरियल व्हीकल, डॉर्नियर विमान तथा अन्य सैन्य साजोसामान उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।'

राजनाथ सिंह ने 'डिफेंस एक्सपो' में पहली इंडिया-अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए संकेत दिए कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सौदों को लेकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिंह ने कहा कि भारत कोशिश करेगा दोनों देश पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में सहयोग दे। उन्होने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच समझौतों की नींव अफ्रीका की आवश्यकताओं की प्राथमिकता होगी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में देश के रक्षा उद्योग ने काफी तेजी से सार्वजनिक-निजी,अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रगति की है जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़कर सबंधों को मजबूत बनाने के अपार संभावनाओं के अवसर प्राप्त हुए है।

उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम

राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पूरा करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश में रेल, वायु मार्ग और रोड की बेहतर कनेक्टिविटी और मंजूरी का एकल विंडो तंत्र बेहतर कार्य कर रहा है।

लखनऊ में भारत-अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव को संबोधित करते राजनाथ सिंह

उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार 17 स्मार्ट व सेफ शहरों में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र बनाएगी। गुरुवार को डिफेंस एक्सपो में रक्षा गलियारे व निवेश को लेकर यूपीडा और फिक्की द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर बन रहे ईस्टर्न और वेस्टर्न गलियारे उत्तर प्रदेश से होकर जा रहे हैं। दोनों का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के बुराड़ी में है। यहां निवेश करने वाले निवेशकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 शहर स्मार्ट ऐंड सेफ सिटी के रूप में विकसित करेंगे जिनके अंदर एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और यहां पर निवेश की अपार संभावनाएं होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में उद्योगपति, निवेश की संभावनाओं में उत्तर प्रदेश के विकास, भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। अगर किसी औद्योगिक संस्थान को खुद को साबित करना है तो उसके लिए भी यहां अच्छे अवसर हैं।'

दिल्ली में 50 फीसदी आबादी को मिली बिजली सब्सिडी

श्रेया जय

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष में दिल्ली की करीब 50 फीसदी आबादी को उनके बिजली बिल में सब्सिडी दी है। सब्सिडी पाने वाली आबादी में से तकरीबन आधे लोगों को पिछले पांच महीने में शून्य रकम वाला बिजली बिल मिला। देश की राजधानी में आप के पांच साल के कार्यकाल के दौरान सब्सिडी पाने वालों की यह तादाद सबसे ज्यादा है। वर्ष 2014-15 में सब्सिडी पाने वालों की तादाद करीब 25 लाख थी। मौजूदा वर्ष में यह तादाद बढ़कर दोगुनी हो गई। दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से ही आप ने लगातार हर साल बिजली दरें घटाई हैं। वर्ष 2015-2018 के दौरान हर साल बिजली बिलों में लगातार तीन बार 50 फीसदी तक की कटौती की गई थी। वर्ष 2018-19 में बिजली बिल 0-200 यूनिट के लिए आधी कर दी गई जबकि 200-400 यूनिट खपत के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भेजा गया और 0-100 यूनिट तक की खपत के लिए बिजली बिल 100 रुपये तय कर दिया गया।

महीना 2019	सब्सिडी पाने वाली आबादी (लाख में)
सितंबर	32.8
अक्टूबर	39.3
नवंबर	45.2
दिसंबर	47.9
जनवरी-20	37.6

दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण, टाटा पावर डेल्ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड कंपनियों के डेटा *स्रोत: वितरण कंपनियां*

इस साल जुलाई में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने मौजूदा योजना के ऊपर सब्सिडी के एक नए मॉडल की मंजूरी दी है। इसके तहत उपभोक्ता के बिजली का तय शुल्क जुलाई में काफी कम कर दिया गया। 2 किलोवॉट तक की तय शुल्क 125 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति किलोवॉट कर दी गई जबकि 2 किलोवॉट से 5 किलोवॉट की श्रेणी में शुल्क 140 रुपये के बजाय 50 रुपये प्रति किलोवॉट कर दी गई। वहीं 5 किलोवॉट से 15 किलोवॉट की तय शुल्क 175 रुपये से घटाकर 140 रुपये कर दी गई। डीईआरसी ने 0-200 खपत वर्ग के लिए 100 फीसदी सब्सिडी दी थी।

किसी भी बिजली बिल में दो चीजें शामिल होती हैं, मसलन हर महीने तयशुदा शुल्क हर महीने समान होती है जबकि बिजली बिल गणना खपत के हिसाब से होती है। नतीजतन मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही सब्सिडी के दायरे में आने वाले लोगों की तादाद दोगुनी हो गई। दिसंबर में सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं की तादाद सबसे ज्यादा करीब 48 लाख तक हो गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1.9 करोड़ है।

कम बिजली खपत वाले घरों में यह फैसला काफी फायदेमंद साबित हुआ। अक्टूबर से दिसबंर तक कम मांग वाले महीने में अनुमानत: 20 लाख लोगों का बिजली बिल शून्य रहा।

कई विश्लेषकों ने इसके लिए सब्सिडी मुहैया कराने की विफल प्रणाली करार दिया। ब्रोकिंग्स इंडिया में फेलो राहुल टोंगिया ने कहा कि फिक्स्ड चार्ज में कटौती से पहले, सब्सिडी प्रतिशत में थी, लेकिन अब यह प्राप्त सब्सिडी के लिए न्यूनतम सीमा के साथ नीचे आई है।

टोंगिया ने कहा, 'इस मॉडल में दो समस्याएं हैं। पहली, सब्सिडी के लिए सीमा बेहद उदार है। इसलिए, कम बिजली खपत वाले कुछ महीनों में इसमें लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ता शामिल होते हैं। इसमें निम्न और मध्य वर्ग शामिल है, लेकिन इसके अलावा वे लोग भी शामिल हैं जो भुगतान कर सकते हैं। दूसरी समस्या यह है कि यह मॉडल बिजली बचत के लिए उपभोक्ता को शून्य रियायत देता है।' आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा है कि वह 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली की 'जन-समर्थक' नीतियों को बरकरार रखेगी। विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव अभियान रियायतों और समाजवाद पर केंद्रित रहा। जुलाई और दिसंबर के ज्यादा मांग वाले महीनों में, दिल्ली की विद्युत मांग 7,000 मेगावॉट से ऊपर पहुंच जाती है, जो बिहार, झारखंड और केरल जैसे राज्यों की पूरी मांग से भी ज्यादा है।

2019-20 के बजट में, आप ने बिजली बिलों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के लिए 1,720 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी। उसने बाद में विभिन्न अनुदानों के लिए पूरक मांगें भी पास कीं जिनमें जुलाई में घोषित अतिरिक्त सब्सिडी को कवर करने के लिए 535 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। उद्योग के जानकारों का मानना है कि सब्सिडी का खर्च लगभग 2,250 करोड़ रुपये होगा, जिसमें हर साल खपत बढ़ने के साथ साथ इजाफा होने की संभावना है।

कोरोनावायरस: चीन का वृद्धि अनुमान कम

रॉयटर्स

जापान ने कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिस जहाज के यात्रियों को अलग रखा था, उनमें से 10 और लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जहाज पर सवार लोगों में से कुल 20 के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ वायरस से फैली इस वैश्विक महामारी के लिए टीका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 563 हो गई है जबकि 28,000 संक्रमण के मामले की पुष्टि हो गई है।

वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के वृद्धि अनुमान में कटौती की है जबकि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वाहन क्षेत्र की बिक्री और उत्पादन में जोखिम की ओर इशारा किया है। उत्साहजनक आर्थिक आंकड़े और अमेरिका से कुछ आयात में चीन द्वारा टैरिफ कटौती की घोषणा करने से वॉलस्ट्रीट बेंचमार्क रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ जिससे वैश्विक स्तर के शेयरों के प्रदर्शन में सुधार दिखा है। चीन ने अमेरिका के 75 अरब डॉलर के सामानों पर लगे दंडात्मक शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती करने की गुरुवार को घोषणा की जिसके बाद बाजार में तेजी देखी गई और विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से उत्साह में बढ़ोतरी हुई है। कोरोनावायरस के प्रकोप से चीन के शहरों और फैक्टरियों को बंद कर दिया गया है साथ ही वैश्विक विमानन सेवाएं भी बंद हो गईं हैं। इस हफ्ते लक्जरी समुद्री जहाज की दुनिया में भी अफरातफरी का माहौल बनता दिखा। कार्निवल डायमंड प्रिंसेज क्रूज पर करीब 3,700 लोग सवार थे जिन्हें जापान के एक बंदरगाह पर कम से कम दो हफ्ते के लिए अलग रखा गया है जहां 20 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और फिलहाल जांच भी जारी है। जापान में अब संक्रमण के कुल 45 मामले सामने आए हैं।

जापान के डायमंड प्रिंसेज क्रूज पर संक्रमण के कुल 20 मामले की हुई पुष्टि

वहीं हॉन्गकॉन्ग के एक जहाज पर 3,600 यात्री और संचालक दल हैं जिन्हें जहाज पर संक्रमण के तीन मामले की पुष्टि होने के बाद दूसरे दिन भी अलग रखा गया है। ताइवान में संक्रमण के 13 मामले की पुष्टि हुई है और अंतरराष्ट्रीय जहाजों को बंदरगाह पर आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्रतिबंध जारी

अमेरिका सहित कई देशों ने पिछले दो हफ्ते पहले तक चीन में रहे यात्रियों को अपने देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। सिंगापुर में मध्य जनवरी में कंपनी की बैठक में वायरस का संक्रमण मिलने की खबर आई है। करीब 94 विदेशी कर्मचारियों के कॉन्फ्रेंस के बाद कम से कम तीन लोगों संक्रमित हुए। इन विदेशी कर्मचारियों में एक व्यक्ति चीन के शहर वुहान से भी था जो कोरोनावायरस का केंद्र बन गया है। अधिकारियों ने कंपनी की पहचान नहीं बताई है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसकी जांच चल रही है। सिंगापुर में संक्रमण के 28 मामले की पुष्टि हुई है जिसमें इंसान से इंसान में फैलने वाला संक्रमण शामिल है।

अमेरिका और चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अगले कुछ महीने में शुरुआती स्तर पर मानव जांच के लिए एक टीका तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। जिनेवा में 11-12 फरवरी को सैकड़ों विशेषज्ञों की बैठक होगी जिसमें ऐसे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों और टीके में शोध की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

कोरोनावायरस से भारत का जीरा, तिल, मूंगफली निर्यात होगा प्रभावित

विनय उमरजी

कोरोनावायरस की महामारी के बीच जहां चीन के बाजार लगातार बंद होते जा रहे हैं, वहीं गुजरात से खासकर जीरा, तिल और मंगफली का निर्यात एक-दो महीने में 10-15 प्रतिशत घट सकता है। कारोबारियों और निर्यातकों के अनुसार, भारत से कुछ प्रमुख जिंसों की खरीदारी में चीन का लगभग 20-30 प्रतिशत के बीच योगदान रहा है। यदि कोरोना को लेकर मौजूदा हालात बने रहे तो इन जिंसों के निर्यात में 10-15 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

अक्सर चीन में लूनर नव वर्ष की छुट्टियों की वजह से जनवरी में चीनी बाजार बंद रहते थे। लेकिन वुहान से कोरोनावायरस की महामारी फैलने के बाद से ऐहतियाती उपाय बरते गए हैं और इस वजह से बाजारों को अभी पुन: नहीं खोला गया है। चीन प्रशासन इस महामारी पर नियंत्रण के प्रयास में लंबे समय तक बाजार बंद रखना चाहता है, जिससे भारत से विभिन्न जिंसों का निर्यात प्रभावित हुआ है। उंझा कमोडिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय जोशी ने कहा, 'सामान्य तौर पर ये छुट्टियां पांच दिन तक रहती हैं। लेकिन अब बाजार को बंद हुए लगभग एक पखवाड़ा हो चुका है। लोग मास्क लगाकर घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। हम वीडियो कॉल के जरिये चीन में जिंस कारोबारियों के संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन वहां स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है और इससे निर्यात 10-15 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकता है। उंझा देश में सबसे बड़े जीरा बाजारों में से एक है।' भारत से लगभग 150,000 टन जीरा हर साल निर्यात किया जाता है, जिसमें एक-तिहाई या 50,000 टन अकेले चीन भेजा जाता है। सामान्य तौर पर 2600 टन जीरे के 10 कंटेनर रोजाना भेजे जाते हैं, जिनमें कोरोना महामारी की वजह से भारी कमी आई है।

चीन के लिए तिल का निर्यात (जिसका कुल तिल निर्यात में 20 प्रतिशत का योगदान) भी प्रभावित हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टेकहोल्डर्स (एफआईएसएस) के चेयरमैन अश्विन नायक के अनुसार, यदि मौजूदा स्थिति बरकरार रही तो चीन को निर्यात 10-15 प्रतिशत तक घट सकता है। नायक ने कहा, 'कुल सालाना तिल निर्यात लगभग 250,000 टन का होने का अनुमान है जिसमें चीन की भागीदारी 20 प्रतिशत है। यदि मौजूदा हालात एक या दो महीने तक बने रहे तो इस निर्यात में बड़ी कमी आ सकती है।' सौराष्ट्र ऑयल मिल्स एसोसिएशन (सोमा) के अध्यक्ष समीर शाह के अनुसार, हालांकि हालात मंगफली तेल निर्यात के मामले में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हैं। शाह ने कहा, 'यदि दीवाली 2019 के पर्व से तुलना की जाए तो पता चलता है कि पहले तीन महीनों में गुजरात से मूंगफली निर्यात पिछले साल के कुल निर्यात को पार कर गया और चीन का इसमें लगभग 90 प्रतिशत योगदान रहा था।' शाह कहते हैं कि हालांकि खरीदारी में कमी आई है, लेकिन चीन के कारोबारियों द्वारा इसके लिए पूछताछ और बातचीत का सिलसिला बरकरार है। नए निर्यात ऑर्डरों को लेकर अनिश्चितता से कपास की कीमतें भी 41,000 रुपये प्रति कैंडी से गिरकर हाल के समय में 39,000 रुपये पर रह गई हैं।

चीन के वुहान में बने अस्थायी अस्पताल में मरीज

चीन गए विदेशियों पर भारत में पाबंदी

अनीश फडणीस

आव्रजन ब्यूरो ने एक नोटिस में कहा है कि जो विदेशी नागरिक जो 15 जनवरी को या उसके बाद चीन गए हैं तो भारत में उनका प्रवेश वर्जित होगा। चीन में कोरोनावायरस के मामले में तेजी आने के बाद यह कदम उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका और कई अन्य देशों ने विदेशी नागरिकों पर ऐसे ही समान प्रतिबंध लगाए हैं।

आव्रजन ब्यूरो के मुताबिक जो विदेशी नागरिक जनवरी के दूसरे पखवाड़े में चीन गए हैं उन्हें हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग या सीमा मार्ग के जरिये प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि विमानन कंपनियों के संचालक दल को इस नियम से छूट दी गई है।

वैसे पहले ही भारत की यात्रा पर आने के लिए चीन के नागरिकों और चीन में रह रहे विदेशियों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यात्रा प्रतिबंध लगाने के बाद भारत और चीन की विमानन कंपनियां भी भारत और चीन के बीच उड़ानें रद्द कर रही हैं। हालांकि ये प्रतिबंध हॉन्गकॉन्ग, मकाऊ और ताइवान के चीनी पासपोर्टधारकों पर लागू नहीं होता।

कोरोनावायरस के प्रकोप से अब तक 560 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 28000 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। केरल में भी संक्रमण के तीन मामले की पुष्टि हो चुकी है। चीन, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और थाईलैंड के यात्रियों की जांच हवाईअड्डे पर स्वास्थ अधिकारी कर रहे हैं।

नागरिक विमानन मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक यात्रियों की जांच एयरोब्रिज से बाहर निकलते ही की जाएगी और स्वास्थ्य अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही आप्रवासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।